चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 17 अक्टूबर- 23 अक्टूबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

आतंकी बता कर जेल में ठूंस देते हैं, जानकारी मांगने पर परिजनों को सताते हैं

ये हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी आतंकवादी

प्रभात रंजन दीन

आतंकवाद को लेकर पूरा देश और पूरा विश्व संवेदनशील है. लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को न संवेदनशीलता से कोई लेना-देना है और न संवेदना से. आतंकवाद के आरोपों में जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लंबा अरसा जेल में काट लेने के बाद अदालतों द्वारा जिन्हें निर्दोष बता कर रिहा किया जाता है, उसकी कोई सूचना न गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध है और न प्रदेश के गृह विभाग के पास. फिर सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास के दावे किस आधार पर कर रही है! यह सवाल नहीं है, बल्कि आधिकारिक तथ्य है, जो सवाल बन कर केंद्र और यूपी सरकार के माथे पर चिपका हुआ है. सबसे सनसनीखेज पहलू यह है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार होने वाले लोगों या निर्दोष साबित होने के बाद रिहा होने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगने पर, जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) या एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) के हवाले कर दिया जा रहा है. यह महज इसलिए कि जानकारी मांगने वाले व्यक्ति के मन में आतंकवाद के मामले में फंसने का मनोवैज्ञानिक डर भर दिया जाए, ताकि वह चुप्पी मार कर बैठ जाए.

आतंकवाद के आरोपों में गलत फंसे लोगों का ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी सरकार के गृह विभाग के पास नहीं है. ऐसे लोगों के निर्दोष साबित होने के बाद रिहा होने का आंकड़ा भी उपलब्ध होने की स्थिति नहीं है. स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों में से किन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला, किन्हें पुनर्वास योजना के तहत लाभ मिला या नहीं मिला और निर्दोष लोगों को फंसाने वाले कितने पुलिस वालों को सजा मिली या नहीं मिली, इसका भी कोई आंकड़ा केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास नहीं है. संदर्भित सूचनाएं मांगने पर गृह मंत्रालय अपने हाथ खड़े कर देता है कि उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है. इसके अलावा आधिकारिक तौर पर गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफाना बयान भी देता है कि आतंकवादी मामलों की जांच एनआईए या राज्य पुलिस करती है, लिहाजा सूचना मांगने वाले व्यक्ति का आवेदन एनआईए के हवाले किया जाता है. साथ ही गृह मंत्रालय यह भी सलाह देना नहीं भूलता कि संबंधित सूचनाएं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पास उपलब्ध हो सकती हैं. प्रधानमंत्री दफ्तर के पास भी ऐसी सूचना नहीं रहती. पीएमओ कहता है, 'मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के अभिलेखों का हिस्सा नहीं है'. प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है कि सूचनाएं गृह मंत्रालय से मांगी जा सकती हैं. लेकिन गृह मंत्रालय से सूचना नहीं मिलती. उत्तर प्रदेश सरकार भी यही नकल करती है. मुख्यमंत्री कार्यालय जानकारी से अनभिज्ञता जता कर आवेदन को गृह विभाग भेज देता है और गृह विभाग उसे गुपचुप तरीके से एंटी टेररिस्ट स्क्वायड के पास अग्रसारित कर देता है. सूचना के अधिकार की मर्यादा समझते हुए दो पंक्ति का जवाब भेजने की भी जरूरत नहीं समझता.

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रेमी सरकार का हाल बुरा है. आतंकवाद के आरोपों में फंसे और रिहा हुए लोगों के बारे में सूचनाएं मांगने पर मुख्यमंत्री कार्यालय अपनी अनभिज्ञता जताता हुआ आवेदन को गृह विभाग के सुपुर्द कर देता है. गृह विभाग उस आवेदन पर कोई जवाब नहीं देता. सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अचानक एंटी टेररिस्ट स्क्वायड की तरफ से हाजिर होने का सम्मन पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं. वह समझ नहीं पाता कि जानकारी मांगने का उसका अधिकार किस कानून के तहत जुर्म हो चुका है! अब वह जानकारी मांगने के बजाय अपनी सफाई पेश करता फिर रहा है और एटीएस अधिकारियों की खुशामद में कोर्निशें बजा रहा है. मुरादाबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग इन्हीं त्रासद स्थितियों से गुजर रहे हैं. ऐसे अनगिनत सलीम बेग हैं, जो सूचनाएं मांगने के चक्कर में अब एनआईए और एटीएस के दफ्तरों के आगे पीछे घनचक्कर हो रहे हैं. बाटला हाउस मुठभेड़ कांड के बारे में सूचनाएं मागने पर आजमगढ़ के विनोद यादव को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसका जिक्र करते हुए वे असहज हो जाते हैं. स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें लखनऊ के चारबाग स्टेशन से उठा लिया और एक हफ्ते तक अपने पास बंधक बनाए रखा. इस दरम्यान वे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े तमाम ऐसे सवाल पूछते रहे, जिसका उनसे कोई प्रसंग ही नहीं बनता था. एसटीएफ के अधिकारी विनोद यादव और उनके साथियों की टेलीफोन पर हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड सुनाकर उसे गलत गतिविधियों से जबरन जोड़ते और प्रताड़ित करते. फिर एसटीएफ ने अपराधियों की तरह अपनी गाड़ी में बैठा कर लगातार दो दिन लखनऊ की सड़कों पर घुमाया.

आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों में सबसे अधिक लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है. इनमें से कई लोग लंबे अरसे तक जेल भुगत लेने के बाद निर्दोष करार दिए गए. लेकिन उनके रिहा होने से उनकी खुशियां थोड़े ही लौट सकती हैं. अपनी उम्र का सबसे अच्छा हिस्सा जेल में बिना कसूर काट लेने के बाद उनमें बचता ही क्या है! उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारों के कार्यकाल के हिसाब से देखें तो मायावती के कार्यकाल में आतंकवादी होने के आरोप में सबसे अधिक लोग गिरफ्तार किए गए. मायावती के कार्यकाल में 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई. इनमें तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, कौसर फारूकी, गुलाब खान, मो. शरीफ, सबाहुद्दीन, फहीम अंसारी, जंग बहादुर, नूर इस्लाम, सज्जादुर्रहमान, मो. अख्तर वानी, याकूब, नासिर हुसैन, नौशाद, जलालुद्दीन, मो. अली अकबर, अज़ीज़ुर्रहमान, शेख मुख्तार, आफताब आलम अंसारी, मुफ्ती अबुल बशर, शहबाज़, बशीर हसन, मो. आरिफ, सलमान, शहज़ाद, हबीब फलाही, मो. सैफ, सैफुर्रहमान, साकिब निसार, हाकिम, ज़ीशान, आरिफ बदर, ज़ाकिर शेख, अफज़ल उस्मानी, इजहार, जियाउद्दीन, मो. आबिद, सादिक शेख, महबूब मंडल और सरवर शामिल हैं. इसी तरह मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में आतंकवादी होने के आरोपों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें आसिफ इकबाल, मो. नसीम, मो. अज़ीज़, शकील अहमद, डॉ. इरफान, मौलाना वलीउल्लाह, महबूब अली, सैयद शोएब हुसैन, फरहान, रिज़वान सिद्दीकी, मो. शाद अली और सैय्यद मुबारक सीतापुर के नाम शामिल हैं. मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव के ताजा कार्यकाल में 16 लोगों को आतंकवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इनमें अमजद, ज़ाकिर, सालिक, महबूब, नजमा, ज़फर मसूद, मौलाना मुफ्ती अबुल समी कासमी, असदुल्लाह अख्तर, आसिफ, मो. अलीम, रिज़वान, फखरुद्दीन, अहमद, वसीम बट, सज्जाद बट और शकील अहमद शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की असलियत यह भी है कि जिन गिरफ्तार लोगों को अदालतों की तरफ से रिहा किया गया, उनकी रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई और रिहाई रुक गई. ऐसे निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए कानूनी से लेकर राजनीतिक-सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले 'रिहाई मंच' के राजीव यादव कहते हैं कि आतंकवाद के नाम पर न केवल प्रदेश के लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, बल्कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मारा भी जा रहा है. बाटला हाउस मुठभेड़ कांड में आजमगढ़ के साजिद और आतिफ अमीन इसी तरह मारे गए. 23 दिसंबर 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को मारने की साजिश रचने के नाम पर कश्मीरी शॉल बेचने वाले दो लोगों को लखनऊ के चिनहट में मार डाला गया था. पुलिस ने उन्हें लश्कर का आतंकी बताया था, जबकि बाद में पाया गया कि वे जाड़े में शॉल बेचने के लिए आने वाले कश्मीरी व्यापारी थे. राजीव कहते हैं कि इसी तरह 25 जनवरी 2009 को नोएडा के सेक्टर 97 में फर्जी मुठभेड़ में दो लोगों को मारा गया, लेकिन उनके बारे में पुलिस ने बताया ही नहीं कि उनके आतंकी होने का सुराग क्या था. इसी तरह लखनऊ के इजहार को वारंगल में फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था.

रिहाई मंच का कहना है कि उत्तर प्रदेश के नौ युवक विभिन्न आतंकी मामलों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है. आजमगढ़ का डॉ. शाहनवाज बाटला हाउस कांड में पकड़ा गया था, लेकिन आज तक लापता है. अहमदाबाद विस्फोट कांड, दिल्ली विस्फोट कांड और जयपुर विस्फोट कांड में शामिल होने और इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस का सदस्य होने के आरोप में पकड़े गए आजमगढ़ के खालिद का भी कोई अता-पता नहीं है. मुम्बई रेल सीरियल ब्लास्ट कांड में पकड़े गए आजमगढ़ के अबु राशिद का भी कुछ पता नहीं चला. आजमगढ़ के ही मोहम्मद आरिज को अहमदाबाद विस्फोट कांड, दिल्ली विस्फोट कांड, जयपुर विस्फोट कांड और बाटला हाउस कांड में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन वह लापता है. इन्हीं कांडों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए आजमगढ़ के मिर्जा शादाब बेग, वासिक बिल्लाह, साजिद बड़ा, मोहम्मद राशिद और शादाब अहमद का भी आज तक कोई अता-पता नहीं चला. इन्हें पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस का सदस्य बताया था.

तकरीबन डेढ़ दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आतंकवादी आरोपों में गिरफ्तार लोग लंबे-लंबे समय तक जेलों में सड़ते रहे, बाद में निर्दोष साबित होकर रिहा हुए लेकिन उन्हें किसी भी पुनर्वास (शेष पृष्ठ 2 पर)

पकड़े गए लोगों की सूचना मांगने पर कर दिया एनआईए और एटीएस के हवाले

निर्दोष साबित होकर रिहा हुए लोगों को कोई राहत या मुआवज़ा नहीं मिलता

गोरे को कश्मीरी आतंकी, प्रेमी जोड़े 'जे-एम' को जैशे मुहम्मद बता दिया

यूपी में जारी हैं किसी भी युवक को आतंकी बता कर जेल में ठूंस देने का आतंक

लेकिन ज़िन्दगी अब भी मुश्किल है | P-3

मराठा क्रांति मोर्चा: आरक्षण आर्थिक बदहाली का हल नहीं है | P-4

कोसी में चलती है भू-माफ़िया की दादागीरी | P-6

ये हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी आतंकवादी

पृष्ठ 1 का शेष

पैकेज का फायदा नहीं मिला और उनकी जिंदगी रिहा होने के बावजूद त्रासदियों में कैद होकर रह गई. लखनऊ के सहकारिता भवन विस्फोट मामले (अपराध संख्या-213/2000) में गिरफ्तार किए गए कलीम अख्तर और सैयद अब्दुल मुबीन के साथ ऐसा ही हुआ. लखनऊ के हुसैनगंज में आरडीएक्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए बिजनौर के याकूब को अदालत ने निर्दोष साबित कर रिहा किया. इसी तरह लखनऊ के नाका थाना इलाके में पकड़े गए बिजनौर के ही नासिर हुसैन और वजीरगंज पुलिस द्वारा पकड़े गए नौशाद को भी अदालत ने निर्दोष पाया. जबकि पुलिस ने इन्हें आरडीएक्स के साथ पकड़ने का दावा किया था. बरेली के सैयद मुबारक, कानपुर के वासिफ हैदर, मुमताज, रामपुर के जावेद, ताज मोहम्मद और मकसूद व लखनऊ के आफताब आलम अंसारी भी लंबा अर्सा जेल में बिताने के बाद निर्दोष साबित होकर रिहा हुए. लखनऊ के वजीरगंज थाने की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जलालुद्दीन उर्फ बाबू भाई, मोहम्मद अली अकबर हुसैन, अजीजुर्रहमान सरदार और शेख मुख्तार को आरडीएक्स के साथ पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में उन लोगों को रिहा कर दिया. लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या राहत पैकेज का लाभ नहीं मिला. केरल के एरनाकुलम में वाघमन में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाने के नाम पर गिरफ्तार किए गए आजमगढ़ के अबू शाद और शाह आलम को भी अदालत ने निर्दोष पाया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया. उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई साक्ष्य ही नहीं पाया गया. अदालत से वे रिहा तो हो गए, लेकिन उन्हें न तो केरल सरकार ने कोई मुआवजा दिया और न उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई खोज-खबर ली.

रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले के आरोप में गिरफ्तार प्रतापगढ़ के कौसर फारूकी समेत कई लोग जेल में बंद हैं, लेकिन उस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही. यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि मामले की तेज सुनवाई की जाए पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ. सिमी के नाम पर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जारी रहा. मुलायम के कार्यकाल में हूजी के नाम पर इलाहाबाद से वलीउल्लाह समेत 12 लोगों की गिरफ्तारियां, मायावती की सरकार में आजमगढ़ के तारिक-खालिद समेत 41 लोगों की गिरफ्तारियां और अब अखिलेश सरकार में मौलाना खालिद (जो हिरासत में मारा गया) समेत 16 लोगों की गिरफ्तारियां इसी का क्रम है. संभल से आसिफ और जफर मसूद को अलकायदा के नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लखनऊ में अलीम और कुशीनगर से रिजवान को आईएसआईएस के नाम पर पकड़ कर जेल में ठूंस दिया जाता है. सिमी और हूजी के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई उनमें से अधिकतर लोग अदालतों से रिहा हो गए, लेकिन न तो उन्हें कोई मुआवजा मिला और न दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई.

अहमदाबाद और लखनऊ धमाकों के आरोपी संजरपुर निवासी आरिफ के परिजन पूछते हैं कि लखनऊ कचहरी धमाके में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी तो फिर बाद की आतंकी घटनाओं में यही नाम कैसे जोड़ दिए गए? इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए, जिसमें पहले की किसी घटना में गिरफ्तारियां हुई और उनके जेल में रहते हुए उन्हें बाद की घटनाओं में भी शामिल दिखा दिया गया. ऐसे ही विरोधाभासी मामले अदालतों द्वारा छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इससे भी प्रताड़नाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सीतापुर के सैय्यद मुबारक हुसैन तो बरेली में फेरी लगाकर शॉल बेचते थे. उनका कसूर यह था कि वे गोरे हैं और उनकी कद-काठी अच्छी है. बस, उन्हें कश्मीरी बता दिया गया और आतंकवाद के आरोप में उन्हें चार साल जेल में बिताना पड़ा. अदालत ने उन्हें रिहा किया. विडंबना यह है कि मुबारक हुसैन की मां जब उनसे मिलने जातीं तो पुलिस उन पर कश्मीर का प्रमाण पत्र लाने का दबाव डालती. सीतापुर के रहने वाले मुबारक हुसैन के बच्चे भी काफी गोरे हैं. अब उन्हें यह डर सताता है उनके बच्चों को भी कहीं पुलिस कभी कश्मीरी आतंकी न बता दे. रामपुर के जावेद को पाकिस्तानी लड़की से प्रेम करने की सजा में लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ा. जावेद की मां पाकिस्तान के अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहती थीं, उसी दरम्यान फोन पर एक लड़की से जावेद की बात हुई थी. जब जावेद अपनी मां के साथ पाकिस्तान गए तो वहां उस लड़की से उन्हें प्रेम हो गया. प्रेम की पेंगों में परस्पर लिखे जाने वाले प्रेम पत्रों में जावेद और मोबीना 'जे-एम' लिखा करते थे. पुलिस ने प्रेमी जोड़े 'जे-एम' को जैशे मुहम्मद बता दिया. मोबीना के उर्दू में लिखे गए खत को हिंदी में अनुवाद करने या जावेद के हिंदी वाले पत्र को उर्दू में लिखने वाले जावेद के दोस्तों सरताज और मकसूद को भी पुलिस ने आईएसआई एजेंट बता दिया और सबको जेल में ठूंस डाला. ■

यूपी की जेलों में बंद यूपी के 'आतंकी'

आतंकवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद मुस्लिम नौजवानों की तादाद काफी है. आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक यह संख्या 32 है. लेकिन जेल विभाग के ही सूत्र बताते हैं ऐसे लोगों की संख्या सौ से ऊपर है, जो प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद हैं. वे किसी मामूली केस में भी अंदर आए तो उनकी जमानत के समय पुलिस उन पर आतंकी गतिविधियों जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लाद देती है और उन्हें जेल में ही घुटना पड़ता है. प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद ऐसे कैदियों का आधिकारिक ब्यौरा यह है...

1. तारिक कासमी, निवासी- आज़मगढ़. लखनऊ कचहरी बम कांड, अपराध संख्या-547/07, थाना- वजीरगंज; फैजाबाद कचहरी बम कांड, अपराध संख्या-3398/07, थाना- कोतवाली सिटी फैजाबाद; बाराबंकी विस्फोट कांड, अपराध संख्या-1891/07, कोतवाली बाराबंकी; गोरखपुर विस्फोट कांड, अपराध संख्या- 812/07, थाना- कैंट गोरखपुर. गोरखपुर मामले में उम्र कैद और शेष में विचाराधीन.
2. खालिद मुजाहिद, निवासी-जौनपुर. लखनऊ कचहरी बम कांड, अपराध संख्या-547/07, थाना- वजीरगंज; फैजाबाद कचहरी बम कांड अपराध संख्या-3398/07, थाना- कोतवाली सिटी फैजाबाद; बाराबंकी विस्फोट कांड, अपराध संख्या-1891/07, कोतवाली बाराबंकी. 18 मई 2013 को खालिद मुजाहिद की पुलिस हिरासत में संदेहास्पद मौत.
3. कौसर फारूकी, निवासी- प्रतापगढ़. बरेली सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, थाना- सिविल लाइन्स, रामपुर. मामला विचाराधीन.
4. जंग बहादुर, निवासी- मुरादाबाद. सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, थाना- सिविल लाइन्स, रामपुर. 11/2/08 से जेल में विचाराधीन.
5. गुलाब खान, निवासी- बरेली. सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, थाना- सिविल लाइन्स, रामपुर. 10/2/08 से जेल में विचाराधीन.
6. मोहम्मद शरीफ, निवासी- रामपुर सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, थाना- सिविल लाइन्स, रामपुर. 10/2/08 को नेपाल से गिरफ्तारी हुई. विचाराधीन
7. सबाहुद्दीन, निवासी- बरेली. सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, थाना- सिविल लाइन्स, रामपुर. दोषमुक्त
8. गुलजार वानी, निवासी- जम्मू-कश्मीर. लखनऊ सहकारिता भवन विस्फोटकांड, अपराध संख्या-213/2000, बाराबंकी, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आगरा से बरी. बाराबंकी कांड में विचाराधीन.
9. फहीम अंसारी, निवासी- महाराष्ट्र. सीआरपीएफ रामपुर गोलीकांड, अपराध संख्या-8/08, 210/08, 209/08, थाना सिविल लाइन्स, रामपुर. 26/11 मुंबईकांड से दोषमुक्त. अन्य मामलों में विचाराधीन.
10. फरहान, निवासी- लखनऊ. लखनऊ बम कांड में उम्र कैद.
11. शोएब, निवासी-लखनऊ. लखनऊ कांड में उम्र कैद.
12. रिजवान, निवासी- अमरोहा. लखनऊ कांड में उम्र कैद.
13. शाद, निवासी- अमरोहा. लखनऊ कांड में उम्र कैद.
14. जियाउद्दीन, निवासी- लखनऊ. चारबाग स्टेशन उड़ाने की धमकी में सजा.
15. सरताज, निवासी- लखनऊ. चारबाग स्टेशन उड़ाने की धमकी में सजा.
16. मोहम्मद वसीम, निवासी-लखनऊ. उम्र कैद
17. वलीउल्लाह, निवासी- इलाहाबाद. गाजियाबाद में मुकदमा चल रहा है. लखनऊ में आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत में हाजिर नहीं किया जा रहा.
18. नूर इस्लाम, निवासी- पश्चिम बंगाल. आरडीएक्स बरामदगी, अपराध संख्या-281/07, थाना- वजीरगंज लखनऊ में बरी. उन्नाव मामले में सजा.
19. सज्जादुर्रहमान, निवासी- जम्मू कश्मीर. लखनऊ कचहरी विस्फोट, फैजाबाद कचहरी बम कांड, गिरफ्तारी 22/12/2007 को हुई. अपराध संख्या 3398/07, थाना कोतवाली सिटी फैजाबाद. लखनऊ मामले में बरी, फैजाबाद मामले में विचाराधीन.
20. मोहम्मद अख्तर वानी, निवासी- जम्मू कश्मीर. लखनऊ कचहरी बम कांड, फैजाबाद कचहरी बम कांड में जेल में विचाराधीन.
21. महबूब मंडल, निवासी- पश्चिम बंगाल. लखनऊ कचहरी कांड में उम्र कैद.
22. अमजद, निवासी- बिजनौर. लखनऊ और बिजनौर धमाका मामले में जेल में विचाराधीन.
23. जाकिर, निवासी- बिजनौर. लखनऊऔर बिजनौर धमाका, विचाराधीन.
24. सालिक, निवासी- बिजनौर. लखनऊ और बिजनौर धमाका, विचाराधीन.
25. महबूब, निवासी- बिजनौर. लखनऊ और बिजनौर धमाका, विचाराधीन
26. नजमा, निवासी- बिजनौर. लखनऊ और बिजनौर धमाका, विचाराधीन
27. आसिफ इकबाल, निवासी- इलाहाबाद. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि हमला. विचाराधीन.
28. मोहम्मद नसीम, निवासी-इलाहाबाद. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि हमला. विचाराधीन.
29. मोहम्मद अजीज, निवासी- इलाहाबाद. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि हमला. विचाराधीन.
30. शकील अहमद, निवासी- इलाहाबाद. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि हमला. विचाराधीन.
31. डॉ. इरफान, निवासी- सहारनपुर. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि हमला. विचाराधीन.
32. अजीजुद्दीन, निवासी- पुणे. लखनऊ कांड में सजायाफ्ता.

दूसरे राज्यों में बंद यूपी के नौजवान

उत्तर प्रदेश के दो दर्जन से अधिक युवक देश के विभिन्न जेलों में आतंकी होने के आरोप में बंद हैं. इन युवकों की रिहाई के लिए कानूनी मदद देने में तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं. इनमें यूपी सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है और युवकों का भविष्य जेल की सलाखों के पीछे अंधकार में डूबता जा रहा है.

1. अबुल बशर, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद सूरत विस्फोट कांड और एरनाकुलम ट्रेनिंग कैंप मामले में एरनाकुलम जेल में बंद.
2. सरवर, निवासी- आजमगढ़. जयपुर विस्फोट कांड में जेल में बंद.
3. शहबाज अहमद, निवासी- लखनऊ. जयपुर विस्फोट कांड में जेल में बंद.
4. सैफ, निवासी- आजमगढ़. जयपुर विस्फोट कांड, बाटला हाउस कांड, अहमदाबाद विस्फोट कांड और गोरखपुर विस्फोट कांड में जेल में बंद.
5. मोहम्मद शकील, निवासी- सीतापुर. दिल्ली विस्फोट कांड, अपराध संख्या-54/11. 12/5/12 को गिरफ्तारी हुई.
6. बशीर हसन, निवासी- संडीला. दिल्ली विस्फोट कांड, अपराध संख्या-54/11. 5/2/12 को गिरफ्तारी हुई.
7. आरिफ, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड, उत्तर प्रदेश कचहरी ब्लास्ट मामले में जेल में.
8. सैफुर्रहमान, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड, जयपुर विस्फोट कांड में जेल में.
9. साकिब निसार, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड, दिल्ली विस्फोट कांड में जेल में.
10. हाकिम, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद और दिल्ली विस्फोट कांड में गिरफ्तार.
11. जीशान, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड और दिल्ली विस्फोट कांड में गिरफ्तार.
12. आरिफ बदर, निवासी- आजमगढ़. पुणे विस्फोट कांड, अहमदाबाद विस्फोट कांड, दिल्ली विस्फोट कांड, मुम्बई रेल सीरियल ब्लास्ट मामले में जेल में.
13. सादिक शेख, निवासी-आजमगढ़. पुणे विस्फोट कांड, अहमदाबाद विस्फोट कांड, संकट मोचन विस्फोट कांड, मुम्बई रेल सीरियल विस्फोट, अमरीकन सेंटर कोलकाता विस्फोट कांड में गिरफ्तार.
14. जाकिर शेख, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड, मुम्बई रेल सीरियर ब्लास्ट कांड में जेल.
15. अफजल उस्मानी, निवासी- मऊ, उ.प्र. अहमदाबाद विस्फोट कांड, मुम्बई रेल सीरियल धमाके में जेल.
16. सलमान, निवासी- आजमगढ़. जयपुर और दिल्ली विस्फोट कांड में बरी. अहमदाबाद विस्फोट कांड और जयपुर विस्फोट कांड में जेल में.
17. शहजाद, निवासी- आजमगढ़. दिल्ली विस्फोट कांड, बाटला हाउस कांड में पुलिस पर फायरिंग. उम्र कैद.
18. हबीब फलाही, निवासी- आजमगढ़. अहमदाबाद विस्फोट कांड में जेल में.
19. असदुल्लाह अख्तर, निवासी- आजमगढ़. दिल्ली विस्फोट कांड, अहमदाबाद विस्फोट कांड, हैदराबाद विस्फोट कांड और मुम्बई विस्फोट कांड में गिरफ्तार.
20. जफर मसूद, निवासी- संभल. अलकायदा का सदस्य होने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार.
21. मोहम्मद आसिफ, निवासी- संभल. अलकायदा का सदस्य होने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार.
22. मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी कासमीसमीउल्लाह, निवासी- टांडा. रामपुर सीआरपीएफ गोलीकांड, दिल्ली विस्फोट कांड में गिरफ्तार. आईएसआईएस का सदस्य होने का आरोप.
23. मोहम्मद अलीम, निवासी- लखनऊ. आईएसआईएस का सदस्य होने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार.
24. रिजवान, निवासी- कुशीनगर. आईएसआईएस का सदस्य होने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार.
25. फखरुद्दीन, निवासी- मिर्जापुर. मोदी की रैली के दौरान पटना गांधी मैदान में धमाका मामले में गिरफ्तार. इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने का आरोप.
26. अहमद, निवासी- मिर्जापुर. मोदी की रैली के दौरान पटना गांधी मैदान में धमाका मामले में गिरफ्तार. इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने का आरोप.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 33
17 अक्टूबर- 23 अक्टूबर 2016
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378
पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आतंक के आरोप से बरी तो हुए

लेकिन ज़िन्दगी अब भी मुश्किल है

आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है. भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देश है और आतंक के ख़िलाफ कई स्तरों पर जंग जारी है. लेकिन इस जंग में कुछ बेकसूर लोग ऐसे फंस जाते हैं या कहें कि फंसा दिए जाते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी ज़िन्दगी जेल की काल कोठरी की भेंट चढ़ जाती है, बल्कि उनसे जुड़े लोगों का भी जीना दूभर हो जाता है. जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, तब तक उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस से बीस साल का समय निकल जाता है. इनोसेंस नेटवर्क ने 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में पीपल्स ट्रिब्यूनल आयोजित कर आतंकवाद के आरोप से बरी कुछ लोगों की दास्तां को सबके सामने लाने की कोशिश की. पेश है चौथी दुनिया संवाददाता शफीक आलम की रिपोर्ट...

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

मो. आमिर

निसारुद्दीन अहमद

वासिफ़ हैदर

- ऐसे गुनाह के लिए 22 साल जेल, जो कभी किया नहीं
- बरी होने के बाद न पुनर्वास हुआ, न मुआवज़ा मिला
- सामाजिक-राजनीतिक तौर पर अब भी बहिष्कृत किए जा रहे हैं
- पुलिस और न्यायिक सुधार है वक्त की ज़रूरत

जेल की सलाखों के पीछे बिताए चौदह साल की कहानी सुनाते-सुनाते मोहम्मद आमिर की आंखें भर आती हैं और आवाज़ भर्रा जाती है. वह कहता है कि फरवरी 1998 की एक रात को वह दवा लेने अपने घर से निकला था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसपर यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास 1996-97 में जितने भी बम धमाके हुए थे, उनमें उसका हाथ था. उस समय आमिर की उम्र 18 साल थी. उस पर टाडा या पोटा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि भारतीय दंड संहिता की आम धाराओं के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया था. वह कहता है कि थर्ड डिग्री टार्चर कर उसे ज़बरन गुनाह कबूल करवाया गया था. उसे जान-बूझकर झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बहरहाल चार्जशीट दाखिल करने और अदालती कार्रवाई में एक निर्दोष नौजवान, जिसने जीवन की दौड़ में अभी क़दम भी नहीं रखा था, को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होने में जीवन के 14 बहुमूल्य साल जेल की काल कोठरी की भेंट चढ़ गए. आमिर कहता है कि इंसान अपने ऊपर हुए जुल्म और दर्द को सह लेता है, लेकिन परिवार पर जो बीतती है, वह असहनीय है और यह चीज़ दुनिया की नज़र से छिपी होती है. यह बात कहते-कहते उसकी आवाज़ भर्रा जाती है कि मेरे वालिद जब नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो उनके परिचित भी उनसे मुंह मोड़ लेते थे. अगर कोई मेहमान मेरे मां-बाप से मिलने आता था, तो स्थानीय पुलिस उसे थाने ले जाकर पूछताछ करती थी. आमिर के जेल जाने के तीन साल बाद पिता की मृत्यु हो गई. उसकी मां अकेले दस साल तक उसकी बेगुनाही की लड़ाई लड़ती रहीं. फिर 2010 में जेल में रहते ही उसकी मां का ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर पैरालिसिस अटैक हुआ और आज से दो साल पहले मां की भी मौत हो गई.

यह दर्द पीपल्स ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवादी वारदातों के आरोप से बरी हुए हरेक शख्स का था. गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक और रिहाई के बाद तक इन सबका अनुभव तकरीबन एक जैसा ही था. इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जान बूझकर बेगुनाहों पर इसका आरोप मढ़ दिया जाए और एक सुस्त रफ़्तार जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर उनके जीवन के सबसे सार्थक दिनों को सलाखों के पीछे बिताने पर मजबूर कर दिया जाए. जाहिर है, इसके लिए जहां पुलिस और जांच एजेंसियां ज़िम्मेदार हैं, वहीं हमारी न्यायिक प्रणाली में भी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है. दरअसल ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए लगभग सभी लोगों ने न्यायपालिका की तटस्थता की तारीफ की और यह भी माना कि वे आज आज़ाद हैं, तो वह केवल अदालत की वजह से. तो क्या न्यायपालिका से इस संबंध में कुछ सवाल नहीं पूछे जा सकते? भारत की न्याय व्यवस्था इस अवधारणा पर आधारित है कि भले ही सौ अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए. पर यदि किसी बेगुनाह को 23 साल तक जेल में सड़ना पड़ जाए और 23 साल बाद उससे कहा जाए कि तुम निर्दोष हो तो उसे क्या कहा जाएगा.

ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए नेसरुद्दीन अहमद को गुलबर्गा कर्नाटक से रेलवे ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था. नेसार कहते हैं कि जब 15 जनवरी 1994 को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो वे फॉर्मेसी फाइनल इयर के छात्र थे. उन्हें अपने सभी आरोपों से बरी होने और खुद को निर्दोष साबित करने में 23 साल का समय लग गया. शायद इतना समय नहीं लगता, अगर अदालत ने अपने पहले के फैसलों की बुनियाद पर सबूतों को देखा होता. नेसार को एक इकबालिया बयान (कंफ़ेशनल स्टेटमेंट) की बुनियाद पर इतने दिनों तक जेल में रखा गया. उनका कहना है कि पुलिस के जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने एक सिजर मेमो (जब्त किए गए सामान और साक्ष्य की लिस्ट) तैयार की थी, जिस पर मेरे दस्तखत नहीं थे, बाद में उसी सिजर मेमो को कंफ़ेशनल स्टेटमेंट बना कर मुझे टाडा में बुक कर दिया गया. सिजर मेमो भी उस कंफ़ेशनल स्टेटमेंट के साथ गलती से चार्जशीट में आ गया. अगर यह गलती नहीं होती तो मैं आज यहां नहीं होता. 1996 में हैदराबाद की टाडा कोर्ट ने मुझे टाडा से डिस्चार्ज कर दिया व कंफ़ेशनल स्टेटमेंट को मानने से इंकार कर दिया. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मानने से इंकार कर दिया और टाडा कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा. फिर सीबीआई ने राजस्थान के ट्रेन ब्लास्ट के लिए उसी कंफ़ेशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर दस साल तक उस केस का ट्रायल चलाया और उसी के आधार पर टाडा कोर्ट अजमेर ने मुझे उम्रकैद की सजा दी. 2004 में फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया और 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 1996 हैदराबाद की टाडा कोर्ट ने जो बात इस स्टेटमेंट के संबंध में कही थी, वही सही है. अब सवाल यह है कि जिस इकबालिया बयान को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ख़ारिज कर दिया है, उसे फिर से ख़ारिज करवाने में इतना लंबा समय कैसे लग सकता है और कोई निचली अदालत उसकी बुनियाद पर कैसे किसी को सजा दे सकती है?

जहां तक पुलिस के रोल का सवाल है, तो इस ट्रिब्यूनल में मौजूद देश के विभिन्न हिस्सों में हुए आतंकवादी हमलों या आतंकवादी गतिविधियों के आरोपों से बरी अब्दुल वाहिद, शोएब जागीरदार, निसारुद्दीन अहमद, ज़हीरुद्दीन अहमद, डॉ. फारूक मक्दूमी, वासिफ हैदर, अब्दुल अज़ीम और हाजी सलीस सभी लोगों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें टार्चर कर उनसे कंफेशनल स्टेटमेंटस लिए और महज़ अपनी जांच की ज़िम्मेदारी से मुक्त होने के लिए उनके निर्दोष होने के बावजूद उनपर चार्जशीट दाखिल कर दिया. कंफेशनल स्टेटमेंट पर सवाल उठाते हुए वर्ष 2001 में कानपुर ब्लास्ट और एडीएम रेवेन्यू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार वासिफ हैदर कहते हैं कि जब कोई आरोपी पुलिस के सामने इकबालिया बयान देता है, तो उसी के ऊपर क्यों मुकदमा चलता है, लेकिन जब वही आरोपी कोर्ट में आकर कहता है कि उसने इकबालिया बयान दिया ही नहीं, तो उसको बिलकुल कंसीडर नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? वासिफ आगे कहते हैं, उन्हें अपने मुक़दमे का फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा. मेरे ऊपर 9 आरोप लगाया गए जिनमें से चार राजद्रोह के थे. जब मेरे केस का फैसला आने वाला था, तब पता चला कि चार्जशीट दाखिल करने में सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई हैं और मुकदमा चला दिया गया है, लिहाज़ा अब फैसला टाला जाने लगा. चार साल तक फैसला नहीं आया. फिर हाई कोर्ट से आदेश लेकर आना पड़ा, तब जाकर ये फैसला आया और मुझे अदालत ने बरी किया. अब सवाल यह उठता है कि इस गलती के लिए किसी न किसी पर तो आरोप तय होना चाहिए?

आतंकवाद के मामले में निर्दोष को आरोपी बनाने के मामले में यह कहा जाता है कि पुलिस गलती से ऐसा करती है. लेकिन वासिफ का मानना है कि यह गलती से नहीं होता. वे कहते हैं कि यह स्टेट की पॉलिसी है. राज्य में सरकार बदलने से भी इस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता. बीजेपी की सरकार में मेरी गिरफ्तारी हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे सजा मिली और बसपा की सरकार में मेरे ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई. वासिफ का यह सवाल भी वाजिब है कि यदि गलती से भी किसी को इतने गंभीर मामले में गिरफ्तार किया जाता है और आरोपी के परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या इसके लिए किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं हो सकती? कैसे किसी निर्दोष को वर्षों जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

जब भी आतंकवाद के आरोप में किसी की गिरफ्तारी की खबर छप जाती है या टीवी पर दिखा दी जाती है तो उसको आतंकवादी मान लिया जाता है. क्योंकि टीवी पर दिखाई गई या अख़बारों में छपी ज्यादातर खबरों में ऐसे मामलों में आरोपी शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सीधे तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति को आतंकी कह दिया जाता है. यहां तक कि आतंकवाद के मामलों से बरी हुए लोगों के लिए भी स्थानीय अख़बार आतंकी शब्द लिखने से परहेज़ नहीं करते. कानपुर निवासी वासिफ हैदर कहते हैं कि आठ साल की अदालती कार्रवाई के बाद जब वे अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से बरी होकर घर आ गए, तो उसी वक्त बनारस में दो ब्लास्ट हुए. वासिफ का कहना है कि कानपुर से प्रकाशित तथाकथित प्रसिद्ध अखबारों दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला ने यह लिखा कि आतंकी वासिफ जेल से छूट कर आ चुका है. उसका बनारस की घटना में हाथ हो सकता है. और ये कि उसके खर्चे कहां से चल रहे हैं, कौन-कौन उससे मिलने आ रहे हैं. बाद में भी उन्होंने अपनी खबरों में आतंकी वासिफ लिखना बंद नहीं किया. फलस्वरूप मुझे और मेरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा. बहरहाल बाद में मैंने उन अखबारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत ने कहा कि चूंकि आपके खिलाफ जांच चल रही थी इसलिए उन्होंने आपके बारे में आतंकी लिखा. कानूनी प्रक्रिया में जब तक किसी मामले में आखिरी फैसला नहीं आ जाता, किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है, उसे आरोपी कहा जा सकता है. चूंकि आतंकवाद एक ऐसा गंभीर और संवेदनशील मामला है, जिसमें न सिर्फ आरोपी व्यक्ति बल्कि उससे संबंध रखने वाले सभी लोगों को भी सामाजिक बहिष्कार से लेकर और कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मीडिया पर कुछ न कुछ अंकुश लगाने की ज़रूरत है.

आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार लोगों को हर तरह के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है. आम तौर पर ऐसे मामलों में नौजवानों को ही गिरफ्तार किया जाता है और उनपर मुकदमा चलाया जाता है. और जब तक वे अदालत द्वारा बरी किए जाते हैं तब तक उनकी उम्र का सबसे बेहतरीन समय खत्म हो गया होता है. तो ऐसे में क्या सरकार को उनके पुनर्वास के लिए कोई क़दम नहीं उठाने चाहिए? 14 साल तक जेल में रहे मोहम्मद आमिर का कहना है कि जब कोई आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसका पुनर्वास किया जाता है, लेकिन पुलिस (सरकार के एक अंग) द्वारा किसी को गंभीर आरोप लगा कर फंसा दिया जाता है और लंबे समय तक उसको जेल में रखा जाता है और जब वह कोर्ट से बरी होता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है.

इस ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने कहा कि हम सब जानते हैं कि टाडा, पोटा और यूएपीए का जांच एजेंसियों द्वारा अक्सर गलत इस्तेमाल होता है. हमारी पुलिस पक्षपातपूर्ण है. पुलिस सुधार की लंबे समय से मांग होती रही है, लेकिन मैं न्यायपालिका की भूमिका से निराश हुआ हूं. अदालत के संज्ञान में लाने के बाद भी कि साक्ष्यों को गढ़ा गया है और बचाव पक्ष के इस दलील को मानने के बाद भी न्यायपालिका ने पीड़ितों के अधिकार की रक्षा नहीं की. आईसीसीपीआर (इंटरनेशनल कोवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट) का हवाला देते हुए जस्टिस शाह ने कहा कि भारत आईसीसीपीआर का हस्ताक्षरकर्ता है और आईसीसीपीआर में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी हिरासत का पीड़ित है, तो उसे मुआवजा हासिल करने का अधिकार है. यहां पर अपनी बात रखने वालों में से बहुतों ने कहा कि वे सामाजिक तौर पर अलग-थलग पड़ गए हैं. उनके लिए नौकरी की संभावना समाप्त हो गई है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन का अधिकार केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि मर्यादित जीवन जीने का अधिकार है. लिहाज़ा अगर गलत मामलों में उनकी मर्यादा छीनी गई है तो उसे वापस की जानी चाहिए. वहीं दूसरे जूरी मेंबर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. जीएस वाजपेयी ने कहा कि 'जो लोग मुक़दमे से बाइज्जत बरी हो चुके हैं और जो लोग अब भी जेलों में बंद हैं, इन सब मुक़दमों का डिटेल स्टडी करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जनहित याचिका दायर करनी चाहिए.' बहरहाल, आतंकवाद या इस तरह के मामले जिनमें आरोपियों को ज़मानत नहीं मिल सकती, के लिए अदालती प्रक्रिया को त्वरित बनाने की आवश्यकता है, ताकि किसी निर्दोष को बहुत दिनों तक जेल में क़ैद नहीं रहना पड़े और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके. साथ में सबूत गढ़ने और झूठे मुकदमे दायर करने वाले जांच अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करनी होगी. साथ ही जो लोग अदालत से बरी हुए हैं, उनका पुनर्वास भी होना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सर्जिकल स्ट्राइक

केवल मनोवैज्ञानिक सफलता

अभिजीत अय्यर मित्रा

एक सैन्य अभियान के मुकाबले पाकिस्तानी क्षेत्र में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक औसत दर्जे का था. ये मान भी लिया जाए कि यह ऑपरेशन उस तरीके से न हुआ हो, जैसा इसे बताया जा रहा है. फिर भी, इस सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत-पाकिस्तान के कम तीव्रता वाले युद्ध के प्रारूप को बदल दिया है. जहां तक शक्ति संतुलन का सवाल है, इसका असर मिला-जुला होगा. लेकिन, शक्ति संतुलन से अधिक इसका असर भू-राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक है.

सबसे पहले, इस बात को लेकर भ्रम है कि वहां वास्तव में हुआ क्या? कई अनसुलझे सवाल भारत के पक्ष में नहीं हैं. इस कहानी को एक सटीक गोलाबारी के रूप में पेश किया गया. फिर, इसने हेलीकॉप्टर सवार कमांडो द्वारा की गई छापेमारी और आखिर में जमीनी हमले का रूप ले लिया.

इनमें से, पहला और आखिरी काम (यानी गोलाबारी और जमीनी छापेमारी) भारत की ओर से पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन इन्हें सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है. विकल्प नंबर दो (यानी हेलीकॉप्टर द्वारा कमांडो हमला) एक प्रमुख विकल्प हो सकता है, लेकिन कई कारणों से ऐसा करना संभव नहीं है.

कारगिल से सबक मिलने के बाद भी, जहां भारतीय वायु सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, भारत ने अपने सैन्य विमानन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपायों में निवेश नहीं किया. इस कार्रवाई में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अत्यधिक अविवेकपूर्ण और उकसाने वाला हो सकता था, यदि पाकिस्तान ने एक या दो हेलीकॉप्टर मार गिराया होता. इस क्षेत्र में पाकिस्तान की वायु सुरक्षा की तैयारियों को देखते हुए इसकी संभावना अधिक थी.

इसी तरह, दो पाकिस्तानी सैनिकों का मारा जाना भी एक सामान्य गोलीबारी का नतीजा है या एक सुनिश्चित क्षेत्र पर की गई एक आम छापेमारी है. यदि कोई यह मान ले कि यह कार्रवाई एक सफल हेलीकॉप्टर छापेमारी थी, तो इसके विजुअल्स (फोटो) सारे शक और शुबहे को खत्म करने में बहुत हद तक सहायक होंगे. आखिरकार जब 1999 के पाकिस्तानी नेवी अटलांटिक (नवल एयर आर्म) को भारतीय वायु सेना ने मार गिराया था, तब उसके मलबे के फोटो और मलबे के कुछ अंश को जमा किया गया था.

शक्ति संतुलन के पहलू से देखें तो यह छापा औसत रूप से ही सफल माना जाएगा. लेकिन इसने दिखाया कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय आक्रामकता के खिलाफ परमाणु हथियारों के प्रयोग का दाव बुरी तरह से नाकाम हो गया है. जाहिर है, जैसा कि भारत की यह सोच रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के बाद भी पारंपरिक युद्ध की संभावना बाकी है, सही साबित हुआ है. इसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को बुरी तरह से डिगा दिया है, जिसके भरोसे पाकिस्तान सोचता था कि वह भारतीय आक्रामकता को नियंत्रित कर सकता है. यह भारत की कमजोरी को दर्शाता था और यह भी जाहिर करता था कि पाकिस्तान ही हमेशा सैन्य पहल कर सकता है. इस मामले में सबसे नकारात्मक पहलू है, भारत द्वारा चुना गया लक्ष्य. पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर रैंक से नीचे के किसी भी सैनिक और भाड़े के आतंकी को भेड़-बकरी से ज्यादा नहीं समझती है. इनके मारे जाने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसके विपरीत, भारत द्वारा इस लक्ष्य का चुनाव पाकिस्तान को भारत में कुछ और आतंकी हमले करने के लिए प्रेरित कर सकता है ताकि जिहादियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सके.

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पर आतंकवादी हमले से रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि उसके ब्रिगेडियर या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को लक्ष्य बनाया जाए. लिहाजा, भारत का यह सर्जिकल स्ट्राइक परमाणु प्रतिरोध के मोर्चे पर तो सफल रहा लेकिन आतंकवादी ताकतों को भयभीत नहीं कर सका.

> पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पर आतंकवादी हमले से रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि उसके ब्रिगेडियर या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को लक्ष्य बनाया जाए. लिहाजा, भारत का यह सर्जिकल स्ट्राइक परमाणु प्रतिरोध के मोर्चे पर तो सफल रहा लेकिन आतंकवादी ताकतों को भयभीत नहीं कर सका. इस छापे की वास्तविक सफलता मनोवैज्ञानिक है. 1980 के दशक के बाद से पाकिस्तान की अभेद्य रणनीति को इस स्ट्राइक ने तोड़ दिया है. पाकिस्तान यह मान रहा था कि भारत परमाणु युद्ध के डर से सार्वजनिक तौर पर सीमा पार छापे नहीं मारेगा या इस तरह का स्ट्राइक नहीं करेगा.

इस छापे की वास्तविक सफलता मनोवैज्ञानिक है. 1980 के दशक के बाद से पाकिस्तान की अभेद्य रणनीति को इस स्ट्राइक ने तोड़ दिया है. पाकिस्तान यह मान रहा था कि भारत परमाणु युद्ध के डर से सार्वजनिक तौर पर सीमा पार छापे नहीं मारेगा या इस तरह का स्ट्राइक नहीं करेगा. पिछले 35 वर्षों से दोनों तरफ सेना के लोग इस तरह के काम करते रहे हैं और उसी तरह से जवाबी गोलाबारी भी होती रही है.

लेकिन भारत ने अतीत में कभी खुले तौर पर इन कार्यों की घोषणा नहीं की. सीमा पार छापे की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति से कहानी बदल जाती है. यदि पाकिस्तान इस ऑपरेशन से इनकार करता है और भारत इसके वीडियो जारी कर देता है तो पाकिस्तानी सेना अपनी वैधता और विश्वसनीयता खो देगी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की चुप्पी भारत को इस तरह के और भी हमले करने के लिए प्रेरित करेगी.

दूसरी ओर, यदि पाकिस्तान इसे स्वीकार कर लेता है तो फिर इसके वायु और रक्षा नेटवर्क पर असुविधाजनक सवाल खड़े हो जाएंगे, जैसा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एबटाबाद पर अमेरिकी छापे के बाद सवाल उठे थे. इसी तरह, यदि पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक को स्वीकार करता है तो उसे अपने परमाणु शक्ति संतुलन की विफलता पर जवाब देना होगा. इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना के मनोबल को पहुंचा नुकसान तो बेहिसाब है.

इससे बढ़कर ये कि इस पहल की वजह से भारत बाहरी मध्यस्थता का लाभ उठा सकता है, एक ऐसा खेल जिसे अब तक सिर्फ पाकिस्तान खेलता रहा है. पाकिस्तान का काम अब तक आतंकी हमले के जरिए तनाव पैदा करना, परमाणु हथियारों के उपयोग की बात करना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप हासिल करना था.

कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने परमाणु बम की धमकी दी और कहा कि भारत एक नियमित ऑपरेशन को राई का पहाड़ बना रहा है. ऐसे में पाकिस्तान अपने जाल में ही फंस गया है. अब न पाकिस्तान अपनी धमकी को अमलीजामा पहना सकता है और न ही सिरफिरे ढंग से कार्रवाई कर सकता है और न ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप के लिए बोल सकता है.

महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस निर्णायक रूप से भारत के समर्थन में आ गए हैं. भले ही, सैन्य कार्रवाई को काफी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत को इससे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसने भारत-पाकिस्तान के बीच के समीकरण को बदल दिया है.■

(लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कंफ्लिक्ट स्टडीज में रिसर्च ऑफिसर हैं)
(साभार: इकोनॉमिक टाइम्स)

मराठा क्रांति मोर्चा

आरक्षण आर्थिक बदहाली का हल नहीं है

चौथी दुनिया ब्यूरो

महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा की चर्चा इन दिनों काफी तेज है. मराठा समुदाय अपनी मांगों के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहा है. मूल रूप से यह आंदोलन कोपर्डी में एक लड़की के बलात्कार के बाद शुरू हुआ था. धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया और अब यह राज्यव्यापी आंदोलन बन चुका है. बलात्कारी को फांसी देने की मांग के साथ-साथ अब एट्रोसिटी एक्ट रद्द करने की मांग भी हो रही है. मराठा आंदोलनकारियों का मानना है कि एट्रोसिटी कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल मराठा लोगों के खिलाफ हुआ है. सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि आर्थिक व सामाजिक तौर पर पिछड़े मराठाओं को आरक्षण दिया जाए. आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल-कालेज में प्रवेश नहीं मिलता है और नौकरी में भी उनकी हिस्सेदारी घट रही है. यदि इस आंदोलन को गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि इस आंदोलन से मूलत: खेती-किसानी करने वाले लोग ज्यादा जुड़े हैं. यह बात सही है कि मराठा समाज मूल रूप से खेतिहर समाज रहा है. लेकिन, धीरे-धीरे महाराष्ट्र में मराठा किसानों की हालत खराब होती गई. इस आंदोलन में अब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों (लागत मूल्य पर अतिरिक्त 50 फीसदी मूल्य को मिलाकर समर्थन मूल्य दिया जाए) को लागू किए जाने की भी बात की जा रही है.

इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह है कि इस रैली का नेतृत्व कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है. हालांकि, रैली में विभिन्न पार्टियों के मराठा नेता शामिल होकर अपना समर्थन दे रहे हैं. यह रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है. इस रैली में सबसे आगे लड़कियां होती हैं और सबसे पीछे ऐसे स्वयंसेवक जो रास्ते में गिरे कचरे को साफ करते हुए चलते हैं. रैली के समापन में लड़कियां जिले के कलेक्टर को जाकर अपना मांग पत्र सौंपती हैं और रैली समाप्त हो जाती है. महाराष्ट्र के तकरीबन हरेक जिले में पिछले एक महीने से इस तरह की रैली हो रही है. मराठा क्रांति मोर्चा की योजना नवंबर महीने में मुंबई में 1 करोड़ लोगों की रैली निकालने की है. इस आंदोलन ने निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में बेचैनी पैदा कर दी है.

इस मोर्चे की मुख्य मांग अब 16 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर है. महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की जनसंख्या करीब 33 फीसदी है. यहां यह समुदाय हमेशा शासन में मुख्य भूमिका निभाता रहा है, लेकिन यह भी सच है कि इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गरीबी-अशिक्षा और बेरोज़गारी से जूझ रहा है. इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है. पिछले 25-30 वर्षों में महाराष्ट्र के किसानों का क्या हाल हुआ है, इसे पूरी दुनिया ने देखा है. यहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. नतीजतन, मराठा समुदाय की हालत भी दिनोंदिन खराब होती चली गई. कोपर्डी की घटना इस मराठा आंदोलन की तात्कालिक वजह जरूर बनी, लेकिन इस आंदोलन के पीछे और भी कई वजहें हैं, जो एक लंबे अंतराल के बाद मुखर होकर सामने आई हैं. गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार ने जल्दी में मराठा आरक्षण पर एक अध्यादेश जारी कर दिया था. लेकिन कानूनी खामियों की वजह से यह अध्यादेश अदालत से निरस्त हो गया. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मराठा समुदाय की बदहाली का एकमात्र उपाय आरक्षण ही है? क्या इस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि आरक्षण का मूल मकसद क्या था और अब क्या हो गया है? आरक्षण आर्थिक बदहाली दूर करने का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता. आरक्षण जब दिया गया था, तब इसका मकसद सत्ता और नौकरी में समाज के वंचित तबकों की हिस्सेदारी को बढ़ाना था यानी, आरक्षण हिस्सेदारी बढ़ाने का औजार था और अब भी है. इससे आर्थिक बदहाली दूर होनी होती, तो आज देश की सत्तर फीसदी आबादी रोजाना 20 रुपए पर गुजारा नहीं कर रही होती. जाहिर है, आर्थिक बदहाली के लिए देश में आर्थिक विकेंद्रीकरण की जरूरत है, ऐसी आर्थिक नीति बनाने की जरूरत है, जिससे देश के आम लोगों तक आर्थिक विकास का फायदा पहुंच सके. सवाल है कि नई आर्थिक नीति (उदारवादी और नवउदारवादी आर्थिक नीति) को लागू हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं. क्या इसका सकारात्मक असर समाज पर, वंचित तबकों पर पड़ा? नहीं, अगर पड़ा होता तो आज जाट, गुर्जर, पटेल और अब मराठा समुदाय को अपने लिए आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता.

मोटे तौर पर आज अगर दलितों की बात करें तो उनकी स्थिति में आरक्षण की वजह से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. उल्टे नई आर्थिक नीति की वजह से उनकी हालत और भी दयनीय हुई है. पूरे आर्थिक व्यवस्था में आज आम लोगों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों की हिस्सेदारी न्यूनतम स्तर पर है. हां, इस देश में नई आर्थिक नीतियों की वजह से कुछ नए औद्योगिक घराने जरूर पैदा हुए हैं, कुछ नए अरबपति जरूर बने हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया हो, ऐसा नहीं है. मराठा आंदोलन को भी ध्यान से देखें, तो इसमें ऐसे लोग अधिक हैं, जो मूल रूप से कृषि क्षेत्र में आई बदहाली के शिकार हैं. विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक के किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है. यह आंदोलन बताता है कि क्यों आज देश की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? आज मराठा आंदोलन है, कल किसी और राज्य में कोई अन्य समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग करता नजर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में बन रहा औद्योगिक माहौल

किसे मिलेगा फ़ायदा!

प्रशान्त शरण

झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा औद्योगिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. राज्य में निवेश का बेहतर माहौल दिखाने के तहत राज्य सरकार फरवरी, 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रही है. इसे सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई के साथ ही विदेशों में रोड शो कर चुके हैं. मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन झारखंड का माहौल बनाने का प्रयास रंग पकड़ने लगा है. सैकड़ों उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जाहिर की है और उनके साथ एमओयू भी हुए हैं. रूस की कंपनी रोसोटोम द्वारा राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा के बाद तो राज्य सरकार अति उत्साह में दिख रही है.

'देर आये दुरुस्त आये' की तर्ज पर रघुवर सरकार ने औद्योगिक घरानों को हर सुविधाएं देने की बात दोहरायी है, उससे लगता है कि इस बार राज्य में औद्योगिक माहौल बनेगा, जिससे औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी. वैसे झारखंड में खनिज व वन संपदा की प्रचुरता और सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने के कारण यह राज्य पहले से ही उद्यमियों की नजर में था. पूर्ववर्ती सरकारों ने भी देशी-विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए, लेकिन जल, जमीन व व्यवस्थागत पेचीदगियों के कारण उनमें से ज्यादातर ने अपने पांव खींच लिए. एमओयू के बाद कई तो वापस ही नहीं आए और कई निवेशकों ने अपने प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए विभागों में दौड़-धूप लगाने के बाद थक-हारकर मुंह मोड़ लिए. नया राज्य बनने के बाद झारखंड का औद्योगिक माहौल छोटे से कालखंड में ही धूमिल हो गया, लेकिन इस बार रघुवर सरकार ने नई सोच और पक्के इरादों के साथ फिर राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने का प्रयास किया है. इस बार लोगों को यह अहसास हो रहा है कि बड़े औद्योगिक घराने यहां उद्योग लगायेंगे. अगर नये प्रस्ताव झारखंड की जमीं पर उतर सके, तो रघुवर सरकार की एक नयी साख बन जायेगी. वैसे इस सरकार ने अडानी समूह को सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराकर एवं विशेष रियायतें देकर दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. हालांकि रघुवर सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई, क्योंकि अडानी को अमित शाह का करीबी माना जाता है और संभवतः पार्टी नेता के दबाव के कारण ही रघुवर सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ा. वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ समय पहले यही माहौल रहता तो अंबानी समूह को झारखंड से अपना बोरिया-बिस्तर नहीं समेटना पड़ता.

पर अब रूसी कंपनी एवं अन्य बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा मिले निवेश के प्रस्ताव से मुख्यमंत्री रघुवर दास अति उत्साहित हैं. उनका मानना है कि उद्योगपतियों को पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता था, पर अब सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली लागू की गई है, जिससे एक ही जगह सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी. औद्योगिक घरानों को राज्य में बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के साथ पूरी सुरक्षा मुहैया करायी जाएगी. उन्होंने यह दावा किया कि राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है. नक्सल समस्या पर भी नियंत्रण कर लिया गया है. उद्योगपति राज्य में बेहिचक निवेश कर सकते हैं. राज्य में खनिज एवं वन संपदा प्रचुर मात्रा में हैं, जिसका लाभ औद्योगिक घरानों को मिलेगा. मुख्यमंत्री का मानना है कि देश-विदेश में जो रोड शो हुए, उसका उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आ रहा है. रूसी कंपनी द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने से झारखंड को भरपूर मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रस्ताव आ रहे हैं जिसके कारण कुछ वर्षों में यह राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा.

मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद उद्योग लगाने के प्रस्ताव आने के साथ ही विरोधी दलों के भी आवाज मुखर होने लगे हैं. झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासी हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उद्योग लगाने के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन बर्दाश्त नहीं होगा. अगर सरकार उद्योगों के लिए यहां की जमीन लेती है तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और एक भी इंच नहीं लेने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार गैर मजरुआ एवं बंजर जमीनों को चिन्हित कर भूमि बैंक बनाए और उद्योगपतियों को दे.

विधानसभा में विरोधी दल के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि औद्योगिक निवेश के नाम पर मुख्यमंत्री देश-विदेश घूम रहे हैं. सरकारी खजाने की लूट हो रही है. वे राज्य में विकास का काम छोड़ उद्योगपतियों को रिझाने में लगे हैं. पहले आधारभूत संरचना विकसित करनी चाहिए. वैसे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री रघुवर दास की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण राज्य में औद्योगिक माहौल बन सकता है. उद्योग स्थापित होने से लोगों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार मुहैया हो सकता है, वैसे चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा समर्थित उद्योगपतियों की नजर झारखंड की खनिज संपदा पर है. वे इसी बहाने खनिज संपदाओं पर कब्जा कर सकेंगे और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को अनुचित लाभ देकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अडानी समूह के लिए पूरी ऊर्जा नीति ही बदल दी

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी टीम के साथ जहां देश के मेट्रो शहरों एवं विदेशों में रोड शो कर रहे हैं एवं उद्योगपतियों को लाने में सफल भी हो रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार कुछ उद्योगपतियों पर ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है. इस कारण वे विवादों में भी घिरते जा रहे हैं. उन्होंने भाजपा के प्यारे उद्योगपति अडानी के लिए पूरी ऊर्जा पॉलिसी ही बदल दी. अडानी समूह गोड्डा में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रहा है. अडानी समूह ने राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया है. औद्योगिक जगत में यह चर्चा जोरों पर है कि अडानी समूह के लिए राज्य सरकार ने ऊर्जा नीति में बदलाव कर दिया है. इसका सीधा लाभ अडानी के पावर प्रोजेक्ट को मिलेगा. दरअसल सरकार ने 2012 की ऊर्जा नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकार उन्हीं पावर प्लांटों से बेरिएवल कॉस्ट पर बिजली लेगी, जिसे सस्ते दर पर राज्य सरकार कोयला उपलब्ध कराएगी. ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार झारखंड में स्थापित पावर प्लांट से उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा. 25 प्रतिशत में से 13 प्रतिशत बेरिएवल कॉस्ट पर और 12 प्रतिशत तय रेट पर. तय दर अमूमन बेरिएवल रेट का लगभग आधा होता है. सरकार के इस नये फैसले से अडानी समूह को सीधे लाभ पहुंचेगा. राज्य सरकार अब सस्ते दर पर अडानी से बिजली नहीं खरीद सकेगी. अडानी के साथ पहले फेज का एमओयू फरवरी 2015 में मुम्बई में हुआ था, इसके बाद फेज-2 के समझौते में कंपनी ने शर्तों में बदलाव के लिए दबाव बनाया. सरकार अडानी समूह को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए नियमों में फेरबदल कर अडानी को सुविधा देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया. अडानी प्रोजेक्ट के साथ विवाद के कारण तत्कालीन ऊर्जा सचिव एसकेजी रहाटे का भी तबादला कर दिया गया था. रहाटे शर्तों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे. अडानी समूह को सस्ते दर पर जमीन मुहैया कराने को लेकर भी राज्य सरकार की जमकर आलोचना हुई थी. ■

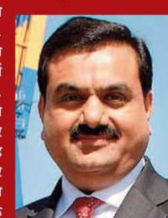

आदिवासियों के हित की अनदेखी न हो - बाबूलाल

झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का मानना है कि राज्य में विकास का काम होना चाहिए, औद्योगिक माहौल बने पर आदिवासियों के हित को अनदेखी कर विकास का काम नहीं हो. अगर बड़े औद्योगिक घराने अपना उद्योग यहां स्थापित करेंगे तो जाहिर है कि आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, इससे आदिवासियों की अस्मिता पर संकट उत्पन्न होगा और जल, जंगल, जमीन छिने जाएंगे, जिससे अपने ही घर में वे बेघर हो जाएंगे. मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को औद्योगिक घराने को आमंत्रित करने के पहले गैर-मजरुआ, गैर कृषि वाली जमीन एवं बंजर भूमि को चिन्हित कर एक भूमि बैंक बनाना चाहिए, ताकि उद्योग के लिए सरकार जमीन मुहैया करा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में आदिवासी एवं गरीब किसानों की जमीन को अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा. इससे पहले भी सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों एवं मूलवासियों को विस्थापित करने का काम कर चुकी है, अब सरकार चेते, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास की विदेश यात्रा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री देश-विदेश की यात्रा पर सरकारी खजाना लुटाने का काम कर रहे हैं. अगर राज्य में छोटे एवं कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया जाता तो अभी तक झारखंड सबसे समृद्ध राज्य बन जाता. यहां की खनिज संपदाओं से दूसरे राज्य शीर्ष पर जा रहे हैं, जबकि हमलोग अपना खनिज लुटाने में लगे हुए हैं. सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है.

नीतीश जी क्या गांधीवाद गुनाह है!

पश्चिमी चंपारण के तीन अंचलों में 500 एकड़ से अधिक भूमि पर भूमिहीनों का कब्ज़ा अहिंसक आंदोलन के कारण संभव हो सका है. शांतिपूर्वक कार्रवाई के दौरान बगहा 1 अंचल के सलहा बरियरवा गांव में सीलिंग से अधिशेष भूमि पर कब्ज़ा हेतु एक भूमि सत्याग्रह का आयोजन 27 जून, 2015 में किया गया था. इस दिन पर्चाधारियों ने धान की फसल लगाई और इसी फसल को 3 नवंबर को काटने के दौरान चौतरवा थाना में सीओ, बगहा 1 ने दर्ज करा दिया. इसके बाद चौतरवा थाना कांड संख्या 282, 03.11.2015 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी ख़ारिज करने के बाद 20 जुलाई, 2016 को सामाजिक कार्यकर्ता पंकज के नेतृत्व में बगहा कोर्ट में हाजिर होकर 19 नामजद में से 13 लोगों ने गिरफ़्तारी दी.

कुमार कृष्णन

चंपारण संघर्ष की भूमि रही है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल 1917 को यहां से सत्याग्रह का आगाज किया था. इस वर्ष सत्याग्रह के सौ साल पूरे हो जाएंगे. शताब्दी को लेकर एक से एक आयोजन हो रहे हैं, पर गांधी का अंतिम आदमी आज भी हाशिये पर है. बिहार में भूमिहीनता सबसे बड़ी विडंबना है. राज्य सरकार की ओर से भूमि सुधार के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कितना सच है इसे बापू की प्रयोगभूमि चंपारण में देखा जा सकता है. गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संकट में हैं.

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 1974 आंदोलन के सेनानी रहे पंकज को सरकारी प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ रहा है. पंकज बिहार राज्य भूमि सुधार व राजस्व विभाग द्वारा गठित भूमि सुधार कोर कमिटी के सदस्य हैं. वे गरीबों और भूमिहीनों के पक्ष में बने भूमि सुधार कानूनों को लागू कराने हेतु विगत दो दशक से लोकतांत्रिक विधि से आंदोलनरत हैं. इन दिनों सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर रखा है.

उन पर एक मुकदमा पश्चिमी चंपारण के बगहा-1 के अंचलाधिकारी ने दायर किया है. यह मुकदमा 3 नवंबर, 2015 को चौतरवा थाना (प्राथमिकी संख्या- 282/15) में दर्ज किया गया है. इस मामले में पंकज व 13 भूमिहीन पर्चाधारी 20 जुलाई, 2016 से बगहा जेल में हैं. इसके पहले पंकज व उनके साथियों के दबाव के बाद 26 साल पुराना केस फिर से 2015 में खुला और पर्चाधारियों के पक्ष में फैसला भी हुआ.

भूस्वामी फिर अपील में राजस्व पार्षद, पटना (वाद संख्या- 17/2016 श्री एसएम राजू के तहत) चले गए हैं.

पश्चिमी चंपारण के तीन अंचलों में 500 एकड़ से अधिक भूमि पर भूमिहीनों का कब्ज़ा अहिंसक आंदोलन के कारण संभव हो सका है. शांतिपूर्वक कार्रवाई के दौरान बगहा 1 अंचल के सलहा बरियरवा गांव में सीलिंग से अधिशेष भूमि पर कब्ज़ा हेतु एक भूमि सत्याग्रह का आयोजन 27 जून 2015 में किया गया था. इस दिन पर्चाधारियों ने धान की फसल लगाई और इसी फसल को 3 नवंबर को काटने के दौरान चौतरवा थाना में सीओ, बगहा 1 ने दर्ज करा दिया. इसके बाद चौतरवा थाना कांड संख्या 282, 03.11.2015 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी ख़ारिज करने के बाद 20 जुलाई, 2016 को सामाजिक कार्यकर्ता पंकज के नेतृत्व में बगहा कोर्ट में हाजिर होकर 19 नामजद में से 13 लोगों ने गिरफ़्तारी दी.

2015-16 में बिहार सरकार के ऑपरेशन दखल दहानी के विशेष कैम्पों के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार प. चंपारण के लगभग दो लाख भूमिहीनों को गैर-मजरूआ मालिक, गैर-मजरूआ आम, भूदान और भू-हदबंदी कानून के अंतर्गत घोषित अधिशेष भूमि का पर्चा मिला है, लेकिन इनमें से लगभग आधे लोगों को पर्चे की भूमि पर कब्ज़ा हासिल नहीं हुआ है. भूमिहीन नागरिक वर्षों से प्रशासन से कब्जे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण क़ानूनी रूप से प्राप्त जमीन पर भूमिहीन अपनी हकदारी से वंचित हैं. हरिनगर चीनी मिल की 5200 एकड़ भूमि भू-हदबंदी कानून के अंतर्गत समाहर्ता, प. चंपारण ने 2007 में अधिशेष घोषित कर दी, लेकिन अभी तक यह मामला राजस्व मंत्री, बिहार सरकार के कोर्ट में लंबित है. सात साल में मंत्री जी का न्यायालय यह निर्णय भी नहीं कर सका है कि यह मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं.

पंकज सहित 18 दलितों की गिरफ्तारी को लेकर देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष है. मोतिहारी स्थित गांधी संग्रहालय में देश के 13 राज्यों के सौ से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नीतीश सरकार से इनकी रिहाई की मांग की है. सरकार की ऐसी कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए राजगोपाल पी.व्ही ने कहा कि पंकज सरकार के वादे के मुताबिक उनकी जवाबदेही को मुकम्मल कराने का काम कर रहे थे. ऐसे में पंकज की गिरफ्तारी से सरकार की कथनी पर संदेह बढ़ता जा रहा है.

पंकज सहित 18 दलितों की गिरफ्तारी को लेकर देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष है. मोतिहारी स्थित गांधी संग्रहालय में देश के 13 राज्यों के सौ से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नीतीश सरकार से इनकी रिहाई की मांग की है. सरकार की ऐसी कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए राजगोपाल पी.व्ही ने कहा कि पंकज सरकार के वादे के मुताबिक उनकी जवाबदेही को मुकम्मल कराने का काम कर रहे थे. ऐसे में पंकज की गिरफ्तारी से सरकार की कथनी पर संदेह बढ़ता जा रहा है.

जलपुरुष राजेन्द्र सिंह और सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी तपेश्वर भाई ने बाकायदा बगहा जेल जाकर पंकज से मुलाकात की और उनकी रिहाई के लिए हाल में जदयू में शामिल स्वामी अग्निवेश से आग्रह किया है कि वे इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात करें और पंकज सहित 18 दलितों की रिहाई सुनिश्चित करें. इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक जन आयोग गठित करने का ऐलान किया है. उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त जज की अध्यक्षता में बननेवाले इस जन आयोग में तीन सदस्य होंगे. यह आयोग पंकज सहित 18 दलितों की गिरफ्तारी के मामले की जांच करेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

कोसी में चलती है भू-माफ़िया की दादागीरी

राजेश सिन्हा

भू माफिया के नाक में नकेल डालने के नाम पर भले ही तरह-तरह की मुहिम चलाई जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भू-माफिया की करतूत के आगे किसी की नहीं चल पा रही है. अगर हम कोसी की बात करें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में हुकूमत चाहे जिस किसी की हो, लेकिन दादागीरी भू-माफिया की ही चलती है. बलकुंडा गांव की कहानी तो एक बानगी मात्र है, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, मोकामा, बेगूसराय सहित कई अन्य इलाकों में गैर-मजरूआ अथवा सरकारी जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई में कई बार भू-माफिया के बीच गोलीबारी हुई है. गैर-मजरूआ अथवा सरकारी जमीन को लेक सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा सहित कोसी की धरती कई बार खून से लाल हुई है. इतना ही नहीं, कोसी के सीने में कई राज भी दफन हैं. सच ये है कि भू-माफिया के आगे न खाकी की चली और न ही खादी की. कोसी इलाके के नहरों व तटबंधों के साथ-साथ रेल पटरियों के आस-पास किसी तरह जीवन गुजार रहे लोगों को कागज पर जमीन तो उपलब्ध करा दी गई, लेकिन कब्जा पाने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं. बलकुंडा गांव निवासी टुनटुन राम कहते हैं कि हमें माफिया की बंदूकों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई बीस एकड़ जमीन पर प्रति परिवार चार डिस्मिल जमीन का खाका खींचकर प्लॉट काट दिया गया है. लेकिन कब्जा दिलाने के नाम पर भू-माफिया द्वारा लाई गई भाड़े की महिलाओं द्वारा की गई बेइज्जती का सामना कर लौटी पुलिस पुनः वापस नहीं आई है. विस्थापित परिवार के लोग अपने नाम से आवंटित खटाल पर झोपड़ी के लिए तंबू-खुट्टा गाड़ ही रहे थे कि भू-माफिया ने विस्थापित महादलित व अति पिछड़े बलकुंडा गांव के विस्थापितों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी. शुक्र है कि गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ. कोसी की बाढ़ व कटाव का दंश झेल चुके बलकुंडा गांव के विस्थापितों की कहानी भी अजीब है. खगड़िया-सहरसा सीमा के आस-पास बसे चौथम थाना क्षेत्र का बलकुंडा गांव महादलितों के साथ अति पिछड़ों का गांव था. बाइस वर्ष पूर्व कोसी ने गांव का भूगोल बदला और देखते-देखते कटाव के कहर से बलकुंडा का अस्तित्व ही मिट गया. पहले बाढ़ ने उजाड़ा, फिर उसके बाद तेज हुए कटाव के कारण चार सौ परिवारों के लोग बेघर हो गए. विस्थापितों को प्रशासनिक मदद मिली और बलकुंडा गांव को पुनर्वासित करने के लिए जमीन की खोज शुरू हुई. चौदह वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद सभी विस्थापित परिवारों को बसाने के नाम पर 1998 में राज्य सरकार ने 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीस एकड़ जमीन अधिगृहीत की. सवाल ये है कि जमीन अधिग्रहण के दौरान आस-पास के जमीन की कीमत बमुश्किल तीन-चार लाख रुपए होने के बाद भी जमीन मालिक को प्रति एकड़ ग्यारह लाख बतौर मुआवजा क्यों दिया गया? नौ जुलाई 2013 को डीसीएलआर, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कई थाना पुलिस या यों कहें कि पूरा सरकारी अमला ही कोसी कटाव प्रभावित बलकुंडा गांव के विस्थापतों को बसाने गया था. लेकिन भू-माफिया की रणनीति के आगे प्रशासनिक रणनीति ने दम तोड़ दिया और प्रशासनिक अमलों को महिलाओं के हाथों बेइज्जत होकर बैरंग वापस लौटना पड़ा. प्रशासनिक अमलों की फौज भू-माफिया की तथाकथित महिला सेना के सामने हार गई. प्रशासनिक अमलों को यह कहकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर अधिगृहित की गई जमीन से भागना पड़ा कि महिला पुलिस की फौज अब माफिया द्वारा एकत्रित की गई महिलाओं से भिड़ेगी और हर हाल में बलकुंडा गांव के कोसी कटाव प्रभावित विस्थापितों को बसाया जाएगा. आशियाने की उम्मीद में जवानी से बुढ़ापे की ओर तेजी से कदम बढ़ाते शिवनंदन सिंह कहते हैं कि आशियाने की लड़ाई में अब जमा की गई राशि भी खत्म होने को है. भू-माफिया के आगे जब सरकार भी विवश है, तो फिर उन जैसे गरीबों की क्या बिसात! शिवनंदन कहते हैं कि दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर किसी तरह अधिगृहीत जमीन पर बस्ती बसाने की मुहिम चलाई गई. लेकिन भू-माफिया द्वारा एकत्रित की गई महिलाएं जमीन पर लेट गईं और पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा. स्थिति यह है कि प्रभावित परिवारों द्वारा अपने स्तर से भी जमीन कब्जा छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन भू-माफिया ने गोली-बारूद व लाठी-डंडों का प्रयोग कर सभी प्रभावित महादलित व अति पिछड़े परिवार के लोगों को खदेड़ दिया. बालकुंडा निवासी जयजय राम, किशुनी राम, जवाहर सिंह, टुनटुन राम, शिवनंदन सिंह आदि कहते हैं कि लगभग चार वर्ष पूर्व जमीन अधिगृहीत किए जाने की जानकारी मिलने के बाद से बलकुंडा गांव के लोगों को आशियाना बनने की उम्मीद थी. लेकिन अभी तक जमीन का नक्शा ही उनके जीवन का सहारा है. 1998 में प्रभावित परिवारों के लिए बीस एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था लेकिन जमीन एक्वायर करने में ही सरकार को चौदह साल लग गए. भू-माफिया सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई जमीन को छोड़ना नहीं चाहता है और सरकारी अमला अधिगृहीत जमीन पर कब्जा दिलाने में समर्थ नहीं दिखता है. विस्थापितों को निशाना बनाकर गोलीबारी करने वाले 22 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद भी गिरफ्तारी तो दूर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. वहीं खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी शिव कुमार शैव का कहना है कि जल्द ही बलकुंडा गांव के विस्थापितों के लिए अधिगृहीत की गई जमीन को कब्जामुक्त कराकर विस्थापित परिवार के लोगों को बसाया जाएगा. वैसे इस तरह के दावे चौथम के अंचलाधिकारियों द्वारा पहले भी कई बार किए गए. चौथम प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कई बार बलकुंडा गांव के विस्थापितों की याद दिलाई गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए. अंचलाधिकारी का स्थानांतरण होने के बाद एक बार फिर बलकुंडा का मामला फाइलों में धूल चाट रहा है.■

आशियाने की उम्मीद में जवानी से बुढ़ापे की ओर तेजी से कदम बढ़ाते शिवनंदन सिंह कहते हैं कि आशियाने की लड़ाई में अब जमा की गई राशि भी खत्म होने को है. भू-माफिया के आगे जब सरकार भी विवश है, तो फिर उन जैसे गरीबों की क्या बिसात! शिवनंदन कहते हैं कि दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर किसी तरह अधिगृहीत जमीन पर बस्ती बसाने की मुहिम चलाई गई. लेकिन भू-माफिया द्वारा एकत्रित की गई महिलाएं जमीन पर लेट गईं और पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा. स्थिति यह है कि प्रभावित परिवारों द्वारा अपने स्तर से भी जमीन कब्जा छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन भू-माफिया ने गोली-बारूद व लाठी-डंडों का प्रयोग कर सभी प्रभावित महादलित व अति पिछड़े परिवार के लोगों को खदेड़ दिया.

feedback@chauthiduniya.com

पहली इस्लामिक बैंकिंग सेवा

मज़बूत होगा लोकतंत्र

ए.यू.आसिफ

ब्याज आधारित कर बोझ के तले दबी हुई दुनिया में पिछले दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर में सहकारिता, विपणन व कपड़ा मंत्री सुभाष देशमुख के लोकमंगल कॉपरेटिव बैंक की बाश्री शाखा में सरकार द्वारा स्वीकृत पहली इस्लामिक बैंकिंग सेवा शुरू हुई. पूरे देश में हर वर्ग के लोगों ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इसका स्वागत किया. इसकी खासियत यह है कि यहां से कर्ज लेने वाले किसी भी शख्स को ब्याज नहीं देना होगा. आइए देखते हैं ब्याज पर आधारित कर्ज व्यवस्था की क्या परेशानियां हैं और एक भाजपा नेता द्वारा की गई इस पहलकदमी की इस देश में आगे बढ़ने की क्या उम्मीदें हैं?

ब्याज किसी व्यक्ति, समाज या देश को किस तरह बरबाद कर देता है, यह किसी से छिपा नहीं है. इसके दो अलग-अलग उदाहरण सामने हैं. उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियर हैं मोहम्मद रईस. लगभग चालीस साल पूर्व उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक (मैकेनिकल) किया. उन्होंने लघु उद्योग मंत्रालय (स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज) से लोन लेकर लोहे का तार बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री खोली. उनका स्वभाव व्यावसायिक के बजाय बौद्धिक ज्यादा था, जिसकी वजह से फैक्ट्री नहीं चल पाई और फिर सरकारी विभाग से लिए गए कर्ज के कारण ब्याज दर ब्याज चढ़ता रहा. आखिरकार नतीजा यह निकला कि इंजीनियर रईस जैसा बुद्धिमान व्यक्ति न घर का रहा, न घाट का. बेहतरीन तकनीकी जानकारी, बौद्धिक और सैद्धांतिक क्षमता होने के बावजूद उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई. दूसरी तरफ जिस संस्था से वे अपने छात्र जीवन से जुड़े थे, वहां से इसलिए निकाल दिए गए क्योंकि कि उन्होंने ब्याज पर आधारित कर्ज लिया था. उसी तरह का एक दूसरा उदाहरण बिहार में दरभंगा के स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल का है. फैजाबाद के मूल निवासी इस्माइल ने दरभंगा में 1960 में बैंक से कर्ज लेकर जूते का एक शोरूम (चैंपियन) खोला और जल्द ही शहर के बड़े व्यापारी बन गए. जब कुछ वर्षों बाद वे समय पर कर्ज नहीं चुका पाए, तो बैंक के कर्मचारियों ने दुकान पर ताला लगा दिया. देखते-देखते वे सड़क पर आ गए. उनका भी हश्र कमोबेश इंजीनियर रईस जैसा हुआ. फर्क सिर्फ इतना था कि उनके बेटे ने पढ़-लिखकर घर संभाल लिया, वहीं अविवाहित होने के कारण इंजीनियर रईस की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई.

ब्याज आधारित कर्ज के तले दबने वाले कई देश भी हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक से लिए गए ब्याज आधारित कर्ज के मारे दस देश हैं, जिनमें अमेरिका सबसे ऊपर है. इस साल की शुरुआत में व्हाइट हाउस के सलाहकार आस्टिन ग्लेस्बी ने चेतावनी दी थी कि अगर नुकसान का यही हाल रहा, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर भयानक असर होगा. मेरा ख्याल तो ये है कि 2008 में हम लोगों ने जिस आर्थिक मंदी को देखा था, उससे भी अधिक खराब स्थिति हो सकती है.

इस संबंध में नाइजीरिया सबसे बदहाल स्थिति में है. अमेरिकी चौधराहट और अंतरराष्ट्रीय सहयोग विषय पर अपनी किताब में कार्ला नार्लोफ कहते हैं कि 2000 में ओकिनावा में आयोजित जी-8 सम्मेलन के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओलो सेगेन ओबा सांजो ने खुले तौर पर कहा था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया में सबसे खराब चीज क्या है, तो मैं कहूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज. राष्ट्रपति ने तब खुलासा किया था कि हम लोगों ने 1985 या 1986 में करीब पांच अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज लिया था. हम अब तक यानी वर्ष 2000 तक ब्याज दर ब्याज के कारण सोलह अरब अमेरिकी डॉलर अदा कर चुके हैं. हमसे कहा गया है कि हमें 28 अरब डॉलर और अदा करना बाकी है. इस स्थिति ने नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया और वह देश भुखमरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. शाह अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय, जद्दा में इस्लामिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट (आईईआई) के प्राध्यापक डॉ. कलीम आलम ने चौथी दुनिया से कहा कि किसी मुल्क की अर्थव्यवस्था पर ब्याज का इससे ज्यादा बुरा प्रभाव और क्या पड़ सकता है?

जहां तक हमारे देश का मामला है, यहां भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. राष्ट्रीय बजट, बैंकिंग सेवा और कॉस्ट अकाउंटिंग के विशेषज्ञ बकार अनवर ने *चौथी दुनिया* को बताया कि 2016-2017 के राष्ट्रीय बजट में 284 हजार करोड़ रुपए कर्ज की राशि रखी गई थी, जबकि 493 हजार करोड़ रुपये ब्याज के तौर पर अदा किए जाने थे. इस तरह दोनों राशि मिलाकर कुल 777 हजार करोड़ रुपए हुए. राजस्व कर और गैर राजस्व कर की आमदनी से हासिल रसीदों का राजस्व 1377 हजार करोड़ रुपये हुआ, कर्ज की अदायगी के लिए मुहैया फंड की सर्विसिंग इस आमदनी की 56 फीसद हुई.

बकार अनवर के मुताबिक इसकी गंभीरता इस हकीकत से समझी जा सकती है कि 534 हजार करोड़ रुपये ताजा कर्ज के मुकाबले पिछले कर्ज की अदायगी कर ब्याज 493 हजार करोड़ रुपये अदा करना होगा. दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ताजा कर्जों के 92 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल पिछले कर्जों की वार्षिक किस्त और सूद की अदायगी के लिए होना है. यह बात कह सकते हैं कि हम नया कर्ज दरअसल पुराने कर्ज की एक साल की किस्त और सूद अदा करने के लिए लेते हैं. लिहाजा हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में या सूद का अभिशाप इतना भयानक हो गया है, जिसका अंदाजा गहराई से सोच-विचार करने पर होता है. सवाल है कि आखिर सूद की यह व्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहां लेकर जा रही है?

किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के लिए उधार लेना-देना बुरा समझा जाता है, लेकिन ब्याज अर्थव्यवस्था का अटूट हिस्सा होने की वजह से जरूरत पड़ने पर कोई भी कर्ज लेने से डरता है. यही वजह है कि किसी भी धर्म या पंथ से संबंध रखने वाले व्यक्ति की नजर जब ब्याज रहित बैंकिंग की अवधारणा पर पड़ती है, तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है और उससे स्वाभाविक रूप से फायदा उठाना चाहता है. लिहाजा पिछले दिनों महाराष्ट्र के भाजपा नेता और सहकारिता, विपणन व कपड़ा मंत्री सुभाष देशमुख ने जब अपने लोकमंगल कॉपरेटिव बैंक की बाश्री शाखा में देश की पहली इस्मालिक बैंकिंग सेवा शुरू करने का औपचारिक ऐलान किया, तो कई लोग इसी बैंक के किसी खाताधारी की जमानत की बुनियाद पर ब्याज रहित कर्ज लेने दौड़ पड़े. पहले दिन 12 लोगों को एक लाख पचास हजार रुपए का ब्याज रहित कर्ज मिला.

इसकी पृष्ठभूमि यह है कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की बात कही थी. रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के समक्ष कुछ दिनों पहले इस तरह की बैंकिंग का प्रस्ताव रखा था. केंद्र सरकार ने उसे 11 सितंबर को स्वीकृति दे दी थी. इस तरह की ब्याज रहित बैंकिंग सेवा की सबसे ज्यादा मुखालफत भाजपा के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी करते रहे हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की पार्टी के सुभाष देशमुख ने इस्मालिक बैंकिंग सेवा की घोषणा की. इसके साथ ही शुरू हुआ ब्याज रहित कर्ज मुहैया कराने का सिलसिला. वैसे छोटे स्तर पर कोई कीमती चीज गिरवी रखकर ब्याज रहित कर्ज लेने का प्रचलन देश के अलग-अलग हिस्सों में है. जमात-ए-इस्लामी हिंद के मरकज़, चितली कब्र (दिल्ली), में भी 1980 के दशक में ब्याज रहित बैंकिग सोसायटी स्थापित की गई थी, जहां से मुस्लिम व गैर मुस्लिम अपनी सोने-चांदी की चीजें गिरवी रखकर कर्ज हासिल करते थे और निर्धारित समय पूरा होने पर रकम वापस करने के बाद अपनी चीजें वापस ले लेते थे. इस सोसायटी के प्रमुख स्वर्गीय मुबारक शाह थे. अब यह सिलसिला बंद हो गया है, लेकिन सुभाष देशमुख का यह प्रयोग कीमती चीजों की गिरवी पर नहीं है, बल्कि उसी बैंक के किसी खाताधारी की दी गई जमानत पर किया जा रहा है.

> किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के लिए उधार लेना-देना बुरा समझा जाता है, लेकिन ब्याज अर्थव्यवस्था का अटूट हिस्सा होने की वजह से जरूरत पड़ने पर कोई भी कर्ज लेने से डरता है. यही वजह है कि किसी भी धर्म या पंथ से संबंध रखने वाले व्यक्ति की नजर जब ब्याज रहित बैकिंग की अवधारणा पर पड़ती है, तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है और उससे स्वाभाविक रूप से फायदा उठाना चाहता है.

सुभाष देशमुख ब्याज रहित बैंकिंग की अवधारणा से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने दूसरी सोसायटियों और बैंकों से इस सिलसिले में उनकी पैरवी करने और इस ब्याज रहित व्यवस्था को अख्तियार करने की गुजारिश की है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार से भी कहेंगे कि वो बेमिसाल और लाभकारी इस बैंकिंग सेवा को स्वीकृति दे दें, जिससे सभी लोग खासकर गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों को फायदा मिल सके. उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मंत्री की यह पहल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई, वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में नए दौर की शुरुआत करेगी और सबका साथ, सबका विकास के नारे को अमलीजामा पहनाने में मददगार साबित होगी.

नेशनल कमिटी ऑन इस्लामिक बैंकिंग और इंडियन सेंटर फॉर फाइनेंस के महासचिव एच. अब्दुर्रकीब चौथी दुनिया से बात करते हुए कहते हैं कि ब्याज रहित इस्लामिक बैंकिंग की अवधारणा ने आम और खास लोगों में जागरूकता पैदा की है. गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे के समय कुछ बड़े आपसी समझौतों पर दस्तखत हुए, जिनमें से एक यह है कि एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस(ओआईसी) के सदस्य देशों के लिए भारतीय निर्यातकों को सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मुहैया कराया जाएगा और दूसरा यह कि आईसीडी, जो इस्लामिक बैंक के अंदर काम करने वाली संस्था है, इसके जरिए एसएमई के विकास के लिए दो सौ करोड़ रुपये की पूंजी पर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी स्थापित करेगी. उम्मीद है कि यह चालू वर्ष के आखिर तक शुरू हो जाएगा. ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था और ब्याज रहित इस्लामी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहली व्यवस्था पूंजीवादी सिस्टम को बढ़ावा देती है और दूसरी लोकतांत्रिक मूल्यों और पद्धति पर आधारित है. ब्याज पर आधारित व्यवस्था में बहुत से लोगों के पैसे कुछ लोगों के हाथों में आ जाते हैं, जबकि ब्याज रहित इस्लामिक व्यवस्था में लाभ और हानि दोनों में कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं. यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो समावेशी है. इस लिहाज से यह सामाजिक न्याय की जरूरत को भी पूरा करता है और लोकतंत्र को मजबूती देता है, जो भारत के संविधान के मुताबिक है. आशा है कि सोलापुर का यह पहला प्रयोग देश में इस्लामिक बैंकिंग की राह को और आसान करेगा और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या है इस्लामिक बैंकिंग

शरियत के उसूलों पर काम करने वाले बैंकिंग व्यवस्था को इस्लामी बैंकिंग कहा जाता है. इसमें किसी तरह का ब्याज न लिया जाता है और न दिया जाता है. इसमें बैंक को होने वाले लाभ को उसके खाताधारियों में बांट दिया जाता है. इस व्यवस्था में बैंकों के पैसे गैरइस्लामी यानी अनैतिक कार्यों में नहीं लगाए जा सकते हैं. ये बैंक या सोसायटी जुए, शराब, बम, बंदूक वगैरह के कारोबार में शामिल लोगों का न खाता खोलते हैं और न ही उन्हें कर्ज देते हैं. कुछ देशों में इस तरह के बैंकों को चलाने के लिए इस्लामिक बैंकिंग-इस्लामी वित्त विशेषज्ञों की एक कमिटी होती है, जो उनका नेतृत्व करती है. आज विश्वस्तर पर इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री का दायरा बढ़कर 1.6 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है. आधुनिक दौर में दुनिया में सबसे पहला इस्लामिक बैंक मलेशिया में स्थापित हुआ था. इस्लामिक बैंकिंग स्कीम के तहत 1993 में कॉमर्शियल, मर्चेंट बैंकों और वित्तीय कंपनियों ने इस्लामिक बैंकिंग प्रॉडक्ट एंड सर्विसेज पेश करना शुरू किया था. भारत में ब्याज रहित बैंकिंग के सबसे बड़े विशेषज्ञों में डॉ. मोहम्मह निजातुल्लाह सिद्दिकी, स्वर्गीय डॉ. फजलू रहमान फरीदी, डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम, डॉ. एमएच खटके, डॉ. ए हसीब, डॉ. शारिक निसार और प्रोफेसर जावेद अहमद खान के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं. इन लोगों ने इस्लामिक बैंकिंग के अलग-अलग पहलुओं पर किताबें लिखी हैं. ■

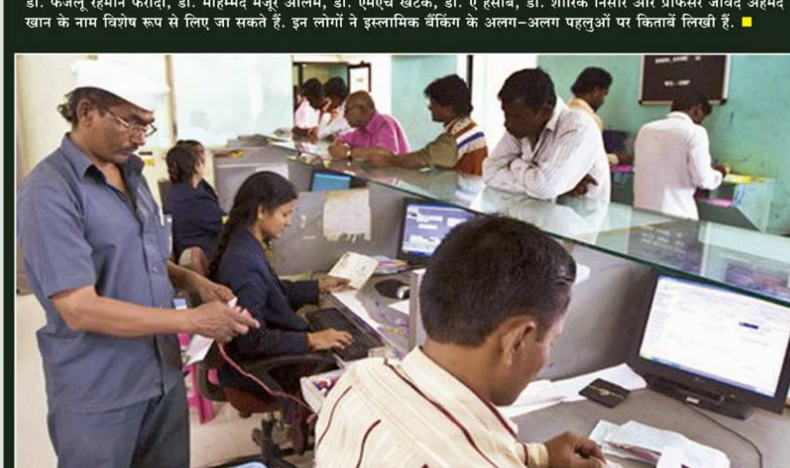

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

पाकिस्तान एक छोटे आकार का देश है, उसकी सेना का आकार भी छोटा है, लेकिन उसके पास भी एक न्यूक्लियर बटन है. हालांकि, उसके पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यह भी मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध को सहन नहीं कर सकते. केवल 4 मिनट के भीतर एक न्यूक्लियर बम मुंबई या दिल्ली को अपना निशाना बना सकता है. इस बारे में कुछ भी कर सकने के लिए इतना समय बहुत कम होता है, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है.

सर्जिकल स्ट्राइक पर सार्वजनिक चर्चा बंद होनी चाहिए

भारत के लोगों ने भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने की खबर को खुशी-खुशी लिया. यह एक अच्छी खबर है, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब सेना ने ऐसा काम किया हो. यह एक नियमित कार्य है. सेना की अपनी एक प्रक्रिया होती है और भारतीय सेना बहुत अधिक पेशेवर, बहुत अधिक सक्षम और बहुत अधिक अनुशासित सेना है. नेताओं का आचरण ही इस प्रकरण का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है. सत्ताधारी दल के कुछ नेता ऐसे शोर मचा रहे हैं, मानो पहली बार कोई रॉकेट साइंस का काम किया हो. दूसरी तरफ, विपक्षी दल संशय की स्थिति में है. कुछ विश्वास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला कर सभी राजनीतिक दल सेना को राजनीति में खींच रहे हैं. कृपया समझने की कोशिश करें, भारतीय सेना अपना काम जानती है, समझती है और करती है. इसका राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है. सेना सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा नहीं करती है कि हमने ये किया या वो किया. यह उनका काम नहीं है.

रक्षा मंत्री, जो प्रधानमंत्री और सेना के बीच के सेतु हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हनुमान है, जो अपनी पूरी ताकत को नहीं जानती. ऐसा लगा मानो सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट भी वो खुद लेना चाहते हों. यह बयान बहुत ही गलत है, सेना का मनोबल गिराने वाला है. निश्चित तौर पर सेना अपने रक्षा मंत्री के व्यवहार और बयान को लेकर चिंतित होगी. मुद्दा ये है कि हमारे पास पाकिस्तान जैसा एक दुश्मन है. पाकिस्तान एक छोटे आकार का देश है, उसकी सेना का आकार भी छोटा है, लेकिन उसके पास भी एक न्यूक्लियर बटन है. हालांकि, उसके पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यह भी मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध को सहन नहीं कर सकते. केवल 4 मिनट के भीतर एक न्यूक्लियर बम मुंबई या दिल्ली को अपना निशाना बना सकता है. इस बारे में कुछ भी कर सकने के लिए इतना समय बहुत कम होता है, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है. पाकिस्तान इस बात को जानता है. पाकिस्तान भारत की तरह एक स्थिर देश नहीं है. उसके पास कोई मजबूत सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है. मुल्ला हैं, जो खून के प्यासे हैं, आतंकी हैं और सेना है. अगर चार लोग सत्ता के लिए लगातार लड़ाई करेंगे, उलझे रहेंगे, तो तार्किक और बेहतर दृष्टिकोण की उम्मीद नहीं की जा सकती है. हमें स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए. लेकिन कम से कम हम ये कर सकते है कि भारत इस बात पर गर्व करता है कि उसके पास एक ऐसी बेहतरीन सेना है, जो सिविलियन लीडरशीप के तहत काम करती है. मौजूदा प्रधानमंत्री सिविलियन नेतृत्व देने में पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी बाध्यता है, जिसकी वजह से मनोहर पर्रिकर को रक्षामंत्री बना कर रखा गया है.

रक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो कम बोलता हो. सेना के लिए उसे प्रेरक होना चाहिए. मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसमें बीजेपी, अमित शाह और अन्य नेता क्रेडिट लें. इससे हमारा मनोबल नहीं गिरता है, लेकिन रक्षा मंत्री, रविशंकर प्रसाद और अन्य अधिकारी टीवी पर अपना सारा समय केजरीवाल की आलोचना करने में बीता रहे हैं और वो भी इसलिए कि केजरीवाल ने सबूत मांगे. ये सब मूर्खतापूर्ण काम है. हमारे पास एक अच्छी सेना है, एक ठीक-ठाक सरकार है, लेकिन ये मूर्ख लोगों के हाथ में है. इस तरह का व्यवहार देश को आगे नहीं ले जा सकता है. पाकिस्तान का मामला ठीक उलट है. वहां गैर जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जब सवाल भारत का आता है, तो सब मिल कर एक साथ भारत के खिलाफ बोलते हैं. हमारे यहां लोकतंत्र है. केजरीवाल ने क्या कहा? यही न कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, इसलिए आप सबूत दिखाकर उसका मुंह बंद कर दें. इस पर इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत थी? आप एक लाइन में अपनी बात रखकर पूरे मामले को शांत कर सकते थे. सरकार कह सकती थी कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन इस पर सार्वजनिक बहस नहीं की जा सकती है. इस तरह की चीजों को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है. लेकिन भाजपा ने यह कहना शुरू किया कि हमने ये किया, वो किया, पहली बार सीमा पार कर के हमला किया. भाजपा ने बड़े-बड़े और गलत दावे करने शुरू कर दिए. आप देश चला रहे हैं. यह एक बहुत ही गंभीर मसला है. यहां सवाल किसी केजरीवाल या सीताराम येचुरी का नहीं है. नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं. उन्होंने एक कैबिनेट का चुनाव किया है, जिसे वो सक्षम लोगों से बना कैबिनेट मानते हैं. उनके मंत्री ऐसे होने चाहिए, जो कम बात करें. वो खुद भी कहते हैं कि मैं काम करने (एक्शन) में विश्वास रखता हूं, लेकिन उनके दोस्त क्या कर रहे हैं? रक्षा और पाकिस्तान के साथ संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. हमारे बीच एक कूटनीतिक संबंध है. आपके नेता पाकिस्तान के उच्चायुक्त को हुर्रियत बोल कर मजाक बना रहे हैं. वे शासन के प्रतिमानों को समझ नहीं रहे हैं. संविधान में शासन के प्रतिमानों का उल्लेख है, यूएन का अपना प्रतिमान है, अंतरराष्ट्रीय सभाओं और समझौतों के अपने प्रतिमान हैं. चाहे कोई भी सरकार हो, इसका पालन किया जाना चाहिए. सर्जिकल स्ट्राइक की एक घटना से लोगों में खुशी का माहौल बना. किस वजह से? वजह ये कि हमने पाकिस्तान को एक संदेश दिया कि वह हमें हल्के में न ले. एक सर्जिकल स्ट्राइक सही संदेश है. ये उकसाने वाला काम नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर न होकर नियंत्रण रेखा पर हुआ है. दोनों पक्ष कश्मीर पर अपना दावा करते हैं. लिहाजा, एलओसी पर फायरिंग का आदान-प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है. सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छी चीज हो सकती है, अगर आपने किया है. लेकिन जिस तरह से इसे लेकर सार्वजनिक चर्चा हो रही है, वो बंद होनी चाहिए. प्रधानमंत्री को एक बयान जारी करना चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, किसी को भी इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मत-मतांतर

भारत-पाकिस्तान महासंघ ज़रूरी

डॉ. राम मनोहर लोहिया

किसी भी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जोड़ने का सिलसिला शुरू करना होगा. मैं यह मानकर नहीं चलता कि जब हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा एक बार हो चुका है तो वह हमेशा के लिए हुआ है. किसी भी भले आदमी को यह बात नहीं माननी चाहिए. हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों का आज यह धंधा हो गया है कि एक-दूसरे की सरकारों को खराब कहें और दोनों ही सरकारें अपने-अपने मुल्क में दूसरे मुल्क के प्रति घृणा का प्रचार करती रहें. दोनों सरकारों के हाथ में इस वक्त बहुत खतरनाक हथियार हैं, लेकिन जनता अगर चाहे तो मामला बदल सकता है.

हिंदुस्तान-पाकिस्तान का मामला, अगर सरकारों की तरफ देखें, तो सचमुच बहुत बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन ऐसी सूरत में भी मैं हिंदुस्तान-पाकिस्तान के महासंघ की बात कहना चाहता हूं. एक देश तो नहीं, लेकिन दोनों कम से कम कुछ मामलों में शुरुआत करें, एक होने की. वह निभ जाए तो अच्छा और नहीं निभे तो और कोई रास्ता देखा जाएगा. सब बातों में न सही, लेकिन नागरिकता के मामले में और अगर हो सके तो थोड़ा-बहुत विदेश-नीति के मामले में, थोड़ा-बहुत पलटन के मामले में एक महासंघ की बातचीत शुरू हो.

यह विचार सरकारों के पैमाने पर आज शायद अहमियत नहीं रखता, मतलब हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे सरकारें तो गंदी हैं. इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि अब इस ढंग से वह सोचना शुरू करे.

अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का महासंघ बनता है तो जब तक मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक के लिए संविधान में कलम रख दी जाए कि इस महासंघ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दो में से एक पाकिस्तानी रहेगा. इस पर लोग कह सकते हैं कि तुम अंदर-अंदर रगड़ क्यों पैदा करना चाहते हो? जिस चीज को पुराने जमाने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले नहीं कर पाए, कभी-कभी कोशिश करते थे, रगड़ पैदा होती थी. अब तुम फिर से रगड़ पैदा करना चाहते हो. इसका मैं सीधा-सा जवाब दूंगा कि 15 बरस हमने यह बाहर वाली रगड़ करके देख लिया, अब फिर अंदर की रगड़ कैसी भी हो, इससे कम से कम ज्यादा अच्छी ही होगी. यह बाहर वाली हिंदुस्तान-पाकिस्तान की रगड़ है, उसको हम निभा नहीं सकते.

हो सकता है कि लोग कश्मीर वाला सवाल उठाएं कि अब तक तो तुमने आसान-आसान बातें कर लीं, लेकिन जो मामला झगड़े का है, इस पर तो कुछ कहो. तो कश्मीर का सवाल अलग से हल करने की जब बात चलती है तो मैं कुछ भी लेने-देने को तैयार नहीं हूं. मेरा बस चले तो मैं कश्मीर का मामला बिना इस महासंघ के हल नहीं करूंगा. मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का महासंघ बनता है तो चाहे कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे, चाहे कश्मीर एक अलग इकाई बनकर इस हिंदुस्तान-पाकिस्तान महासंघ में आए. पर महासंघ बने कि जिससे हम सब लोग फिर एक ही खानदान के अंदर बने रहें. इस महासंघ के तरीके पर बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान-पाकिस्तान की जनता सोचना शुरू करे.

हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक ही धरती के अभी-अभी दो टुकड़े हुए हैं. अगर दोनों देशों के लोग थोड़ी भी विद्या-बुद्धि से काम करते चले गए तो दस-पांच बरस में फिर से एक होकर रहेंगे. मैं इस सपने को देखता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से किसी न किसी इकाई में बंधे. मैं फिर कहता हूं कि भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच एक महासंघ बनाने की आवश्यकता है. मैं मानता हूं कि भारत-पाकिस्तान का बंटवारा अनावश्यक है और अगर जनता चाहे तो दोनों देशों के बीच अमन कायम हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हो सकता है कि लोग कश्मीर वाला सवाल उठाएं कि अब तक तो तुमने आसान-आसान बातें कर लीं, लेकिन जो मामला झगड़े का है, इस पर तो कुछ कहो. तो कश्मीर का सवाल अलग से हल करने की जब बात चलती है तो मैं कुछ भी लेने-देने को तैयार नहीं हूं. मेरा बस चले तो मैं कश्मीर का मामला बिना इस महासंघ के हल नहीं करूंगा. मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का महासंघ बनता है तो चाहे कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे, चाहे कश्मीर एक अलग इकाई बनकर इस हिंदुस्तान-पाकिस्तान महासंघ में आए.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश इस पहेली का उत्तर जानना चाहता है

मुझे किसी मित्र ने सवाल भेजा है, सवाल क्या, बल्कि पहेली भेजी है. मैं इस पहेली का उत्तर नहीं तलाश पा रहा हूं और मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है. मदद इसलिए चाहिए ताकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर मेरे जैसे लोगों को ये बता सकें कि इसका कोई उत्तर है भी या नहीं या आपके दिमाग का वो कोना जो सोया हुआ है, इसका उत्तर तलाश पाता है या नहीं. पहेली शुरू होती है उरी हमले से कि क्या उरी हमले के पर्दे के पीछे भारत सरकार के एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति ने एक उद्योगपति को और बड़ा उद्योगपति बनाने के लिए खजाना उड़ेल दिया. 59 हजार करोड़ रुपये का सौदा चुपके से किस उद्योगपति की झोली में डाल दिया गया?

उरी हमले का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? हम, जो 125 करोड़ लोगों के देश हैं, जिनके पास इतनी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, वो आने वाले हमलावरों या आतंकियों का सुराग नहीं लगा सकतीं. हालांकि हम अथाह पैसा सिर्फ जासूसी पर खर्च करते हैं, लेकिन हमले के बाद भी हम अब तक कोई सुराग क्यों नहीं लगा सके कि हमारे भीतर के वो कौन लोग थे, थे भी या नहीं, जिन्होंने हमलावरों की मदद की और उन्हें रेड-कारपेट बिछाकर सेना के कैंप पर हमला करने का रास्ता दिया. वो कौन लोग थे, जिन्होंने हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई रोक दी, ताकि तारों को आतंकवादी या हमलावर आसानी से काट सकें? वो कौन लोग थे, जिन्होंने उरी में खाली बैरक होते हुए भी सेना के जांबाज जवानों को फ्यूल डंपिंग के पास टैंट लगाने की इजाजत दी? जैसे ही फ्यूल डंपिंग में ब्लास्ट हुआ, टैंट में लिपटकर ये जिंदा जल गए. वो कौन अफसर था या कौन सर्वशक्तिशाली व्यक्ति था जिसने उरी कैंप की सुरक्षा में रात में दस लोगों को भी ड्यूटी पर नहीं लगाया था?

अब उरी हमले का जिक्र अचानक मीडिया से क्यों गायब हो गया? क्या इसके पीछे भी किसी का इशारा है, क्योंकि उरी हमला हमारी कमजोरियों की जीती-जागती मिसाल है. उरी में 18 जवानों की शहादत हमें हमारी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी नहीं चेताती. क्या उरी हमले से हमने कोई सीख ली है?

क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि उरी हमले के तुरंत बाद हमारी सरकार ने एक कंपनी से 59 हजार करोड़ के युद्धक जहाज खरीदने का सौदा कर लिया और हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति की कंपनी, इस कंपनी की मुख्य यानी 55 प्रतिशत की साझेदार बन गई. क्या उरी में सैनिकों पर हमला होने के तुरंत बाद ऑर्डर दिया गया, ताकि जनता में गुस्से की भावना पैदा कर या युद्ध का माहौल निर्मित कर एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके. इतनी तत्परता इसलिए दिखाई गई, ताकि देश की दूसरी कंपनियों को इस सौदे की खबर भी न हो और वो इसमें हिस्सा लेने की हिम्मत भी न जुटा पाएं. उरी हमले का देश को जबरदस्त नुकसान हुआ, आदमियों के रूप में और भावना के रूप में भी, सम्मान के ऊपर हमला हुआ, लेकिन इस हमले में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे देश के किस बड़े उद्योगपति को इसका फायदा हुआ और सरकार में किन लोगों को इसका बड़ा फायदा हुआ? क्या ये भी गलत है कि ये युद्धक जहाज पहले से बहुत महंगी दरों पर खरीदे गए और देश को इससे कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है.

क्या ये गलत है कि अब अचानक उसी घराने का दूसरा सपूत भी युद्धक जहाज के कारोबार में आ गया और इनको भी कई हजार करोड़ के युद्धक जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा. आने वाले त्योहारों में फिर से हमला होने की आशंका जताई जा रही है और कहीं पर कोई वारदात हो गई तो और युद्धक जहाज खरीदने का सौदा इस दूसरे औद्योगिक घराने को दिए जाएंगे.

ये भी एक संयोग है कि इस बड़े उद्योगपति के टेलीविजन चैनल हैं और अखबार भी और लगभग देश के हर बड़े मीडिया में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है. ये सारे चैनल और अखबार देश में दूसरी पार्टियों के खिलाफ लोगों को भड़काने में बुरी तरह से लगे हैं.

वो कौन उद्योगपति है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री पर मॉडलिंग का आरोप लग रहा है. पांच घंटे में प्रधानमंत्री को मॉडल बनाकर सारी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने वाला ये औद्योगिक घराना कौन सा है? वो कौन सा घराना है, जिस पर देश की सवा लाख करोड़ की गैस चुराने का आरोप लगा है और जिस आरोप को अखबार और मीडिया देश के सामने नहीं रख रहे हैं क्योंकि अधिकतर मीडिया घरानों में इस उद्योगपति की हिस्सेदारी है. क्या इस उद्योगपति के 75 हजार करोड़ गुजरात सरकार ने माफ कर दिये हैं और सबसे बड़ी चीज कि क्या इस उद्योगपति के साले को रिजर्व बैंक का गर्वनर बना दिया है. और इससे भी बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इस औद्योगिक घराने पर जुर्माना लगाया तो उसकी फाइल ही गायब हो गई.

हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत मशहूर वक्तव्य दिया था. मैं एक बनिया हूं और व्यापार मेरे खून में है. प्रधानमंत्री जी के इस बयान का इस्तेमाल कर क्या कुछ लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं और हम देशोन्माद में आकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं. इस पहेली के उत्तर आपके पास हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस पहेली का उत्तर मुझे भेजेंगे. मैं आपसे एक कविता और साझा करना चाहता हूं. ये मुझे किसी ने भेजी है. जिसने भेजी है, अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ये कविता लगता है कि आपको बतानी चाहिए.

युद्ध होता है
सरकारें नहीं, सैनिक लड़ते हैं युद्ध
राजा नहीं, प्रजा लड़ती है युद्ध
कुछ सैनिक इस देश के मरते हैं
कुछ सैनिक उस देश के मरते हैं
फिर सुलह होती है
समझौता होता है
संधि होती है और फिर
सब शांत हो जाता है
लेकिन इतना भर नहीं है युद्ध
युद्ध बहुत सारे काम करता है
युद्ध राजनीति भी करता है
युद्ध महंगाई को न्यायोचित ठहराता है
युद्ध गड़बड़ाते हुए जनाधार को रोकता है
युद्ध गिरती हुई साख को थामता है
युद्ध खिसकती हुई कुर्सी को संभालता है
युद्ध घोटालों को भुलवा देता है
युद्ध जासूसी कांड को छुपा देता है
युद्ध सुसाइड नोट को दबा देता है
युद्ध तड़ीपार को बचा देता है
युद्ध ध्यान भटका देता है
युद्ध होते नहीं हैं
युद्ध निर्मित किए जाते हैं
युद्ध गढ़े जाते हैं
उसके चरित्र की परिभाषा की जाए
जो इस देश को भी हथियार बेचता है
जो उस देश को भी हथियार बेचता है
और फिर दोनों से कहता है
शांति से रहना सीखें

मैं आज इस संपादकीय में आपसे राय चाहूंगा और ये अनुरोध करूंगा कि क्या हम कुछ सच्चाइयों को देखने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम ये पहचान सकें कि हमारे अपने देश में कमजोरियां कहां-कहां हैं और हम उन्हें भी पहचान सकें जो इन कमजोरियों का हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर लूट की एक बड़े ग्रंथ की भूमिका लिख रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत मशहूर वक्तव्य दिया था. मैं एक बनिया हूं और व्यापार मेरे ख़ून में है. प्रधानमंत्री जी के इस बयान का इस्तेमाल कर क्या कुछ लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं और हम देशोन्माद में आकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए नारेबाज़ी कर रहे हैं. इस पहेली के उत्तर आपके पास हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस पहेली का उत्तर मुझे भेजेंगे.

» »

उरी हमले का अब तक कोई सुराग़ क्यों नहीं मिला? हम, जो 125 करोड़ लोगों के देश हैं, जिनके पास इतनी बड़ी ख़ुफ़िया एजेंसियां हैं, वो आने वाले हमलावरों या आतंकियों का सुराग़ नहीं लगा सकतीं. हालांकि हम अथाह पैसा सिर्फ जासूसी पर ख़र्च करते हैं, लेकिन हमले के बाद भी हम अब तक कोई सुराग़ क्यों नहीं लगा सके कि हमारे भीतर के वो कौन लोग थे, थे भी या नहीं, जिन्होंने हमलावरों की मदद की और उन्हें रेड-कारपेट बिछाकर सेना के कैंप पर हमला करने का रास्ता दिया. वो कौन लोग थे, जिन्होंने हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई रोक दी, ताकि तारों को आतंकवादी या हमलावर आसानी से काट सकें? वो कौन लोग थे, जिन्होंने उरी में ख़ाली बैरक होते हुए भी सेना के जांबाज़ जवानों को फ्यूल डंपिंग के पास टैंट लगाने की इजाज़त दी?

पाठकों की दुनिया

कश्मीर की सच्चाई

कवर स्टोरी-ये जुल्म की इंतिहा है (03 अक्टूबर- 09 अक्टूबर 2016) पढ़ा. काफी अच्छी है. दिल्ली से तीन वरिष्ठ पत्रकारों का एक दल कश्मीर की हक़ीक़त समझने और उसे देश के सामने लाने के लिए कश्मीर गया था, जिन्होंने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से बातचीत की है. उन्होंने अलगाववादी नेता की मांगों और कश्मीर को लेकर उनके नजरिए को देश और सरकार के सामने रखा है जो एक अच्छा कदम है. जिस प्रकार सैयद अली शाह गिलानी ने पत्रकारों के सामने अपनी बातें रखीं, उसी प्रकार उन्हें कश्मीर आए सर्वदलीय प्रतिनिधमंडल के सामने भी अपनी बातें रखनी चाहिए थीं. लेकिन उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधमंडल से मिलने से मना कर दिया. यह कोई बड़ा मसला नहीं. अब जब उन्होंने अपनी बातें इन पत्रकारों के माध्यम से देश और सरकार के सामने रखी हैं, तो सरकार को इस पर सोचने और समझने की जरूरत है. अगर उनके द्वारा कहीं हुईं बातें सच हैं? तो यह सच में जुल्म की इंतिहा है.

-फिरोज आलम, *वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

सरकार नीति बदले

हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं कश्मीरी (03 अक्टूबर- 09 अक्टूबर 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में जफर इकबाल महनास ने कश्मीर की समस्या को लेकर चर्चा की है. मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कश्मीर का मसला कश्मीर में नहीं, दिल्ली की गर्दिश में खो गया है. आप कश्मीर में जितनी मर्जी हो समाधान खोज लो. इस मसले का हल दिल्ली में है. यह बिल्कुल सही है कि कश्मीर का हल दिल्ली में है और दिल्ली में बैठे नेताओं को कश्मीर का हल निकालने की जरूरत है. सरकार कश्मीर की जनता से बात करे और पूछे उनकी समस्या क्या है? वह क्या चाहते हैं? सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए, तभी तो जनता अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा पाएगी. सरकार को कश्मीरियों को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार उनके साथ है. कश्मीर की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर और केंद की दोनों सरकारें उनके हर समस्या का समाधान निकलानी चाहती हैं और वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगी.

-अरशद आगा, *जामिया, दिल्ली.*

चौथी दुनिया
ये ज़ुल्म की इंतिहा है

मज़बूत नेतृत्व की ज़रूरत

आलेख-रक्षा मंत्रालय ख़ुद संभाले प्रधानमंत्री (03 अक्टूबर- 09 अक्टूबर 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. कमल मोरारका ने बिलकुल सही कहा है कि अपनी पार्टी को किरकिरी से बचाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को इस मंत्रालय को खुद अपने हाथों में ले लेना चाहिए. भारतीय सेना को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और मनोहर पर्रिकर इस मामले में फेल साबित हुए हैं. उनके रक्षा मंत्री रहते पठानकोट हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर का मामला जहां पर पाकिस्तान लोगों के उकसाने और भड़काने में कामयाब रहा, अब उड़ी हमला जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और इससे हमारी कमजोर रक्षा तैयारियों का पता चलता है. रक्षा मंत्री के कई ऐसे बयान भी आए जो उनको नहीं देने चाहिए थे. यह बात भी सही है कि सुरक्षा बलों के तीनों प्रमुख अपनी अच्छी तैयारी और उच्च मोनबल के लिए जाने जाते हैं. जाहिर है, पिछले दो वर्षों में कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है, तभी तो हम उन्हें इस हालत में पा रहे हैं. जितनी जल्दी इस प्रवृत्ति को ठीक किया जाए, उतना ही बेहतर होगा. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्रालय अपने हाथ में हाथ ले लेना चाहिए या किसी मजबूत व्यक्ति को यह मंत्रालय सौंप देना चाहिए.

-कविता पाठक, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

कश्मीरी भी अपने ही हैं

संतोष भारतीय की संपादकीय जब तोप मुकाबिल हो, प्रधानमंत्री जी, कश्मीर और पाकिस्तान दो अलग सवाल हैं (03 अक्टूबर- 09 अक्टूबर 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिलकुल सही कहा है कि कश्मीर का सवाल, कश्मीर की समस्याएं और कश्मीर की तकलीफ अलग है और पाकिस्तान की समस्या अलग है और पाकिस्तान के व्यवहार का सवाल अलग है. पाकिस्तान में एक नाकाम और कमजोर सरकार है जो आतंकवादियों पर रोक नहीं लगा पा रही है. अगर देखें, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों और सेना का राज कायम है. वहां आतंकवादी खुलेआम घुमते हैं और सरकार उनके आगे नतमस्तक है. हमें कश्मीरियों की चिंता करनी चाहिए और उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि सरकार और देश के लोग उनके खिलाफ नहीं हैं. कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए. कश्मीर के लोगों के साथ भी देश के दूसरे राज्यों के लोगों की तरह ही व्यवहार होना चाहिए. उनके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को लगे कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती है. **-रोमा बनर्जी,** *मालदा, पश्चिम बंगाल.*

संयम बरतने की ज़रूरत

भारत पर जब भी आतंकी हमला होता है, वह भारत की सम्प्रभुता पर हमला होता है. देश के 125 करोड़ लोगों के मन एक गुस्सा होता है और लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं. लेकिन इस समय सोच विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है. युद्ध कभी विकल्प नहीं हो सकता और युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए. उसके पहले भारत को कई दूसरे कदम उठाने चाहिए, जैसे सरकार ने हाल के दिनों में जरूरी फैसले लिए हैं. हमें समझना होगा पाकिस्तान कभी न मित्र रहा है और न रहेगा. पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग-थलग करना होगा जो हमारे प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं. युद्ध से दोनों देशों को भारी क्षति पहुंचेगी जिसकी भरपाई करने में सालों गुजर जाएंगे. सरकार को कुटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को मात देनी चाहिए जिससे वह पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ जाए. यह ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध किसी चीज का स्थायी समाधान नहीं है.

-राजेन्द्र शुक्ल, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

शराब समाज का दुश्मन है

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कुछ सवाल उठाए थे और इसके कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. बिहार में पूर्ण शराबबंदी को छह महीने होने को है और इस दौरान छिटपुट विरोध को छोड़कर बड़े पैमाने पर बिहार की महिलाओं और आम लोगों ने पूर्ण शराबबंदी का समर्थन ही किया है. जिस तरीके से शराब बिहारी समाज के भीतर घुसकर उसे खोखला बना रहा था, वैसे में पूर्ण शराबबंदी ही इस रोग का एकमात्र इलाज था. नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर पूर्ण शराबबंदी का एक साहसिक फैसला लिया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए. ■

- राकेश यादव, *मोकामा, बिहार*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

सुरेश चौहान
feedback@chauthiduniya.com

दल बदल नेता

किसी ने खाई मलाई और किसी का हाथ ख़ाली

राजनीति समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम एवं मंच माना जाता है, लेकिन कुछ राजनेता सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राजनीति में आते हैं. उनका लक्ष्य समाज सेवा नहीं बल्कि येन-केन-प्रकारेण विधायक या सांसद बनना होता है. कुछ नेता धैर्यपूर्वक समाजसेवा में लगे रहकर मतदाता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं जबकि अधिकांश नेता सिर्फ अवसरवाद में विश्वास करते हैं. राजनीति में प्रवेश करते ही विधायक/सांसद बनने का स्वप्न देखने लगते हैं और इस स्वप्न को साकार करने के लिए दल बदल का सहारा लेते हैं. ऐसे राजनेता राजनीति से अधिक अवसरवादी होते हैं.

सर्वप्रथम दल-बदल करने का श्रेय वर्तमान भाजपा सांसद डॉ. भोला सिंह के नाम अंकित है. वहीं सर्वाधिक पार्टी बदलने का ताज सुदर्शन सिंह के सिर पर है. डॉ. भोला सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया. भाकपा के समर्थन से विधानसभा का उप चुनाव लड़े और विजयी हुए. बाद में भाकपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े और पराजित हो गए. भाकपा में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होते देख भाकपा को तलाक देकर कांग्रेस की गोद में आ गए. लगभग 20 वर्षों तक वे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए. विधायक निर्वाचित हुए. बिहार सरकार के मंत्री भी बने. कांग्रेस में अपनी दाल गलते नहीं देखकर पुनः पाला बदलते हैं और राजद की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं. लेकिन महत्वाकांक्षा पूरी न होने पर फिर भाजपा की शरण में आ जाते हैं. भाजपा में पुनः उनके भाग्य का पटल खुलता है. विधायक निर्वाचित होते हैं और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं. इस समय वह बेगूसराय से भाजपा के सांसद हैं. उसके बाद कई नेताओं दलबदल की नीति अपनाई, लेकिन इस नीति में एक मात्र जमशेद अशरफ भाग्यशाली निकले. वह कांग्रेस, लोजपा के बाद पाला बदलकर जदयू में चले जाते हैं और विधायक निर्वाचित होते हैं. नीतीश सरकार में मंत्री बनते हैं, लेकिन

नीतिगत मतभेद की वजह से मंत्रीपद एवं जदयू की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं. पुनः दलबदल कर कांग्रेस पार्टी में आ-जाते हैं. विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और पराजित हो जाते हैं. वे अपनी अंदर की महत्वाकांक्षा की वजह से एक बार फिर पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वह इस समय भाजपा के सदस्य हैं.

इसी कड़ी में एक नाम शंकर सिंह का है. युवक कांग्रेस के नामचीन नेता और इंदिरा गांधी के स्नेहपात्र शंकर विधयाक बनने की ललक में भाजपा में शामिल हो जाते हैं. शंकर सिंह को भाजपा जिला अध्यक्ष बना देती है. लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से दल-बदलकर जदयू में शामिल हो जाते हैं. इसी प्रकार कांग्रेस के नेता रहे चितरंजन प्रसाद सिंह अलग-अलग पार्टियों से होते हुए हम(सेक्यूलर) में शामिल हो जाते हैं और अब उसके समर्पित सदस्य हैं.

इसी प्रकार कांग्रेस के नेता अनिल कुमार सिंह अपनी महात्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अलग-अलग पार्टियों में गए, लेकिन जब महात्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया. प्रो. राम बदन राय जनता दल से राजनीति में प्रवेश करने के बाद, राजद, जदयू के रास्ते अब भाजपा में शामिल हो गए हैं. भालो सिंह के नाम दलबदल करने वाले नेताओं में पहले नंबर पर है, लेकिन सर्वाधिक दल-बदल शिरोमणि का ताज तो सुदर्शन सिंह के सिर पर है.■

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सोखोदेवरा सर्वोदय आश्रम

जिसे भूल गए जेपी के अनुयायी

आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पार्टी की करारी हार के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी. इसके बाद वे विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गये थे. इसी दौरान नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड के एक जमीनदार ने जयप्रकाश नारायण को करीब तीस एकड़ भूमि दान में दी. इसी भूमि पर जयप्रकाश नारायण ने ग्राम निर्माण मंडल नामक संस्था और सर्वोदय आश्रम बनाया.

सुनील सौरभ

कभी बड़े-बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लगता था

सरकार के पास खादी छूट का 1.10 करोड़ रुपये बक़ाया है

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड स्थित सर्वोदय आश्रम में कभी देश के बड़े-बड़े नेताओं, बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लगता था. जेपी के निधन के बाद भी कुछ दिनों तक यहां के सर्वोदय आश्रम में देश के नामी गिरामी लोगों का आना-जाना लगा रहा. जेपी के अनन्य सहयोगी और खादी पुरुष के नाम से चर्चित त्रिपुरारी शरण भी जब तक जीवित रहे, तब तक उनके अनुरोध पर देश-प्रदेश के खादी, सर्वोदय तथा राजनीति से जुड़े लोग यदा-कदा आते रहे, लेकिन त्रिपुरारी शरण के निधन के बाद जेपी द्वारा स्थापित यह सर्वोदय आश्रम और ग्राम निर्माण मंडल एक तरह से अनाथ हो गया है. विपरीत परिस्थितियों में भी ग्राम निर्माण मंडल के कार्यकर्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी त्रिपुरारी शरण के सपनों को सकार करने में लगे हैं. जेपी के सर्वोदय और ग्राम निर्माण मंडल की उपेक्षा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार के पास आज भी इस संस्था के करीब एक करोड़ दस लाख रुपये खादी छूट के बकाया हैं. राज्य सरकार यदि आजादी के बाद देश में स्वदेशी सामग्री का निर्माण करने वाली जेपी की संस्था पर जरा सा भी ध्यान देती, तो लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था. सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश और राज्य में शीर्ष पर पहुंचे अधिकतर राजनेता अपने को जेपी का अनुयायी बताते हैं, लेकिन इन नेताओं को जेपी द्वारा स्थापित सोखोदेवरा आश्रम की स्थिति को देखने का समय तक नहीं है. जेपी की पुण्यतिथि या जयंती पर सर्वोदय आश्रम में उनके अनुयायी और किसी राजनेता को वहां जाने की फुर्सत नहीं है. सर्वोदय आश्रम के पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि जेपी जब यहां रहते थे तो बड़े-बड़े राजनेताओं का यहां जमावड़ा लगा रहता था. जेपी के निधन के बाद भी विपक्ष के कई नेता, जो आज देश और राज्य की राजनीति में ऊंचाई पर हैं, उनका आश्रय स्थल यह आश्रम हुआ करता था. हालांकि शासन और राजनीतिज्ञों की उपेक्षा के बाद यहां के कार्यकर्ता तन-मन से जेपी के सपनों को साकार करने में लगे हैं. आज भी ग्राम निर्माण मंडल पूरे मगध प्रमंडल में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में खादी, सिल्क और ऊनी वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इस सर्वोदय आश्रम में खादी, रेशमी और ऊनी कपड़ों की बुनाई, कटाई में सैकड़ों बुनकर और कतिन लगे हुए हैं. इसके अलावा ग्राम निर्माण में यहां के कार्यकताओं का महत्वपूर्ण योगदान है. यही कारण है कि इस आश्रम के आसपास के सैकड़ों गांव में लोगों के रहन-सहन, गौ पालन तथा खेती करने के तरीके में व्यापक रूप से असर पड़ा है.

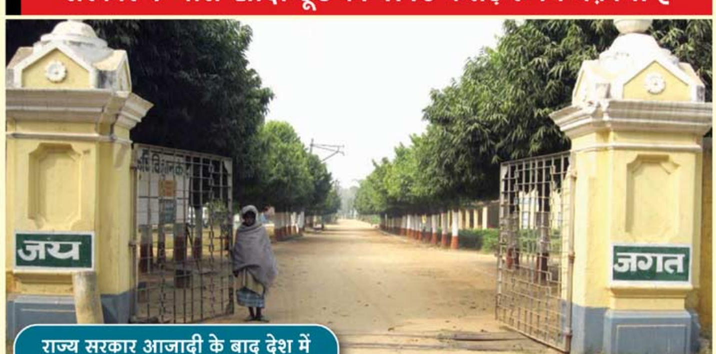

राज्य सरकार आजादी के बाद देश में स्वदेशी सामग्री का निर्माण करने वाली जेपी की इस संस्था पर जरा सा भी ध्यान देती, तो लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था. सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश और राज्य में राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे अधिकतर राजनेता अपने को जेपी का अनुयायी बताते हैं, लेकिन इन नेताओं को जेपी द्वारा स्थापित सोखोदेवरा आश्रम की स्थिति को देखने का समय तक नहीं है. जेपी की पुण्यतिथि या जयंती पर इस सर्वोदय आश्रम में उनके अनुयायी और राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचे किसी राजनेता को वहां जाने की फुर्सत नहीं है.

आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पार्टी की करारी हार के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी. इसके बाद वे विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गये थे. इसी दौरान नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड के एक जमीनदार ने जयप्रकाश नारायण को करीब तीस एकड़ भूमि दान में दी.

इसी भूमि पर जयप्रकाश नारायण ने ग्राम निर्माण मंडल नामक संस्था और सर्वोदय आश्रम बनाया. जेपी के इस क्षेत्र से लगाव का मुख्य कारण यह था कि आजादी की लड़ाई में उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था. 1942 में वो हजारीबाग जेल से फरार होकर जंगल के रास्ते से नवादा पहुंचे थे. जहां उन्होंने शरण ली थी, वह पहाड़ और जंगल सेखोदेवरा गांव के निकट ही था. जेपी ने ग्राम निर्माण मंडल के बाद बिहार का काला पानी कहे जाने वाले कौवाकोल में विकास को ऐसी गति प्रदान की कि लोगों की मेहनत से यहां की बंजर भूमि में हर तरह की फसल लहलहाने लगी. लोगों का रहन-सहन बदल गया. खादी के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, लेकिन आज यह आश्रम अपने समर्पित कार्यताओं से गुलजार तो है, लेकिन शासन, प्रशासन की उपेक्षा से अपने आप को ठगा सा महसूस करता है. खादी पुरुष त्रिपुरारी शरण के निधन के बाद तो राज्य के नेताओं से सीधे संवाद करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचा जो लोग इस संस्था की नियामक समिति में हैं, वह भी संस्था की बैठक तक में अपने को सीमित रखते हैं.

ग्राम निर्माण मंडल के प्रधान अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि आज भी जेपी के प्रति यहां के कार्यकताओं की अपार श्रद्धा है, जिससे यही संस्था जेपी के सपनों को साकार करने में लगी है. गया में इस संस्था से जुड़े खादी ग्रामोद्योग समिति के मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि पहले यहां बड़े-बड़े नेता आते थे और जेपी के प्रति श्रद्धा समर्पित करते थे. लेकिन अब यदा-कदा ही कोई नेता यहां आता है. इतना जरूर हुआ है कि राज्य सरकार ने खादी पुरुष स्वर्गीय त्रिपुरारी शरण द्वारा आविष्कार किए गए एक साथ सूती, रेशमी और ऊनी सूत की कटाई करने वाले त्रिपुरारी मॉडल चरखा का बड़ी संख्या में ऑर्डर दिया है. इस चरखे से बुनकरों और कतिन की आमदनी 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगी. इस मॉडल चरखा का निर्माण ग्राम निर्माण मंडल द्वारा ही किया जाता है. अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि राज्य सरकार और खादी बोर्ड से मिलकर बुनकरों और कतिन को अधिक से अधिक संख्या में त्रिपुरारी मॉडल चरखा उपलब्ध कराएं जिससे खादी कपड़ों के निर्माण और बिक्री से बुनकरों को अधिक लाभ मिल सके. इससे जेपी के सपनों को

साकार करने में हम सभी को सफलता मिलेगी. सरकार की उपेक्षा का आलम यह है कि सर्वोदय आश्रम की भूमि पर बने रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के बदले सीआरपीएफ के जवानों का कब्जा है. इसी प्रकार इस क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए बना कपसिया कुष्ठ आश्रम राशि के अभाव में वर्षों से बंद पड़ा है. अपनी उपेक्षा के बाद भी ग्राम निर्माण मंडल के कार्यकर्ता जेपी के आदर्शों को अपने तन-मन में ढालकर उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पित की थैली की बिमारी ईलाज और बचाव

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
आप सभी को दिपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ.सरयु प्रसाद शर्मा
फिजिशियन, चर्च रोड गया

पित की थौली की बिमारी मगध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। यह बिमारी उस स्थिति में और घातक सिद्व होती है जब कि आप इसके इलाज में कोताही बरत रहे होते हैं। यदि आपको निम्न लक्षण महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें और सही ईलाज करवायें यह मूलतः दो कारणों से होता है। पित की थोली में सूजन तथा पित की थैली में पत्थर। का होना। अधिकतर मरीजों को पित की थैली में पत्थर ही होता है। इसके लक्षणों में उल्टी आना भुख नहीं लगना , गैस फार्म (ढकार आना) इस बिमारी के उपचार के लिए दवाएं भी उपलब्ध है लेकिन समय के साथ ये दवायें भी कम असरदार हो जाती है। इस बिमारी से पूर्णत सही होने के लिए ऑपरेशन सबसे जरूरी माना गया है। इस बिमारी के उपचार के लिए सिलिप्लेक्स, यूरिस्लीव, तथा एरीजोल डी आदि दवाएं मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर दे सकते हैं। ■ प्रस्तुति: चित्रा भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, अवैध कब्ज़ा करने में भी माहिर हैं गायत्री प्रजापति

अमेठी को उमेठ कर रख दिया

■ गायत्री के कारनामों से आगामी चुनाव में सपा को होगा भारी नुक़सान ■ अमेठी की पंगु पुलिस भी कर रही गायत्री के आदेशों का पालन

डॉ. पंकज सिंह/रवींद्र सिंह

विवादों के केंद्र गायत्री प्रजापति से अमेठी आक्रांत है. एक तरफ तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके अनुज शिवपाल यादव हर दिन मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने में लगे होने की शिकायत भी करते हैं और ऐसे नेताओं को संरक्षण भी देते हैं. यही नेता समाजवादी पार्टी का भट्ठा भी बैठा देंगे.

ताजा मामला अमेठी से विधायक व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर है. मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद पुनः वापसी कर अपने आपको और दमदार समझने वाले भ्रष्टधन्य गायत्री प्रसाद प्रजापति अपनी मां गया देवी के नाम डिग्री कॉलेज का निर्माण अमेठी के बाईपास स्थित बघवरिया गांव में करा रहे हैं. वहां इन्हीं की जमीन से सटी बनमानुष जाति (महादलित) के राम फेर पुत्र झुरहू का 8 बिसवे का रकबा भी है. जोकि अब धीरे-धीरे मंत्री गायत्री प्रजापति के पुत्रों द्वारा महाविघालय परिसर के अंदर कर ली गई है और राम फेर को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवाकर वहां से भगा दिया गया है.

महाविद्यालय परिसर के अंदर दलित राम फेर का जर्जर मकान

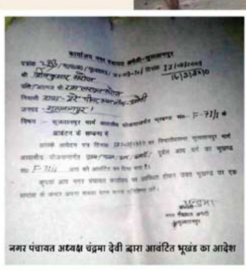
नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी द्वारा आवंटित भूखंड का आदेश

बताते चलें कि रामफेर को कुछ सालों पहले इंदिरा आवास प्राप्त हुआ था. जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था और दोना-पत्तल बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण भी करता था. राम फेर के परिवारीजनों का आरोप है कि गायत्री व उनके पुत्रों द्वारा हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है. जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो गायत्री के पुत्र अनिल प्रजापति व उनके गुर्गों ने मेरे पूरे परिवार को मारा पीटा व मेरे घर पर कब्जा करके हम लोगों को घर से बेघर कर दिया. हम लोग किसी तरह वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंचे तो अमेठी पुलिस हमारी मदद के बजाय उलटे हमें ही जेल भेजने की धमकी देने लगी और कहा कि जमीन मंत्री जी के नाम कर दो और यहां से पलायन कर जाओ. पीड़ित ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग से लेकर अमेठी के सभी आलाधिकारियों से की. परंतु मंत्री के हनक के आगे किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं उठाया.

इतना ही नहीं इसी महाविद्यालय से जुड़े बैंक कर्मी हौसला तिवारी की 14 बिसवा जमीन भी महाविद्यालय परिसर के अंदर जबरदस्ती ले ली गई है. जब इसकी शिकायत हौसला ने पुलिस से की तो हौसला के साथ भी पुलिस प्रशासन ने वही बर्ताव किया जो मंत्री के दबाव में अन्य के साथ करती आ रही है. पीड़ित हौसला तिवारी ने बताया कि जब कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ तो पूर्व दिशा में हमारी नाली गई थी. जिसमें ट्यूबवैल का पानी जाता था. उसे तोड़कर उस पर पिलर बना दिया गया. उसके बाद उत्तर दिशा में निर्माण शुरू हुआ वहां भी हमारी चक पड़ती थी. जब मैंने विरोध शुरू किया तो उन्होंने कहा यह सब मेरा है. हौसला ने बताया कि जो गाटा संख्या 115 है वह तालाब में दर्ज है. उसको कब्जा करते हुए मेरा गाटा संख्या 112 भी कब्जा कर लिया गया और 32 फुट डामर रोड भी बना ली गई. जब मैंने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो उलटे मुझे ही धमकी देकर व डांटकर भगा दिया गया. निर्माण के समय मैंने इस पर अदालत का स्थगन आदेश भी लिया है. परंतु न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है. हौसला ने निराश होकर कहा इसकी शिकायत मैंने अमेठी के आलाधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक की परंतु कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई.

तीसरा ताजा मामला सुल्तानपुर मार्ग पर दुर्बल आयवर्ग के अंतर्गत दलित शिवकुमार सरोज के भूखंड पर अवैध कब्जे का है. शिवकुमार सरोज को 2009 में नगर पंचायत अमेठी द्वारा दुर्बल आयवर्ग का भूखंड संख्या एफ-71/1 आवंटित किया गया जो अभी भी शिवकुमार के नाम आवंटित है. परंतु इसी भूखंड पर दूसरे समुदाय की महिला मकान का निर्माण करवा रही है जब इसकी सूचना शिवकुमार के पुत्र अभय कुमार को मिली तो अभय ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकने की बात कही. फिर भी जब निर्माण कार्य नहीं रुका तो अपनी फरियाद लेकर अभय अमेठी प्रशासन के पास पहुंचा जहां उसे भी वही मिला जो अन्य फरियादियों को मिलता आया है. पीड़ित अभय ने बताया कि मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिपहसलार विजय पाल उपाध्याय ने हमें जमीन छोड़ देने की धमकी दी थी. जब हमने उनकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने जबरदस्ती दूसरी समुदाय की महिला के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करवाना शुरू कर दिया.

दलित शिवकुमार सरोज की जमीन पर अवैध रूप से मकान का निर्माण

जिसके बाद मैंने उपजिलाधिकारी अमेठी व प्रभारी कोतवाली अमेठी से न्याय की गुहार की. बदले में मुझे इन अधिकारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी भी दी गई. इतना ही नहीं मैं न्यायालय से स्थगन आदेश भी लाया. बावजूद इसके पुलिस प्रशासन न्यायालय के आदेश को ताक पर रख कर मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का पक्ष ले रही है. अब गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनको पुत्रों का तांडव अमेठी की जनता के लिए तो असहनीय हो रहा है साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के गले की फांस भी बनता नजर आ रहा है. इस तरह गायत्री प्रसाद प्रजापति जमीन पर अवैध कब्जा करने व भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

डेंगू ने खोल दी यूपी सरकार की पोल

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा करती रही है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप फैला और अस्पतालों में अराजकता का वातावरण पैदा हुआ उससे सभी सरकारी दावों की पोल खुल गई है. समाजवादी सरकार संतुलित एवं समावेशी विकास का दावा करती है लेकिन हालात बद से बदतर हैं, यही असलियत है. प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की लम्बी कतारें लगी हैं. लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री और अफसर मस्ती में हैं. अस्पतालों में घनघोर अराजकता का वातावरण है. मरीजों की सिलसिलेवार मौतों पर आए दिन हंगामे हो रहे हैं. ऐसे संवेदनशील समय में लैब तकनीक कर्मचारी संघ हड़ताल पर चला जाता है, काम ठप्प हो जाता है, लेकिन सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती. इस वजह से स्थिति खराब होती जा रही है. प्रदेश में चुनाव आने वाला है, सभी दल चुनाव की तैयारी में लगे हैं. विरोधी दल भी उसी में मशगूल है. डेंगू जनित बीमारियों और उनके फैलते प्रकोप का मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों को पूरी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष तलब कर लिया है. मीडिया में फजीहत होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने की जरूरत समझते हैं और लखनऊ के महापौर को शहर की साफ-सफाई का ध्यान आता है.

मरीज तो आम आदमी है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं हैं. इस अराजकता और अफरातफरी में अस्पतालों में हर प्रकार के दलाल भी सक्रिय हो गए हैं. ये दलाल अस्पतालों में मरीजों की भर्ती कराने से लेकर उनको रक्तदान कराने व दवाईयां आदि तक दिलाने के लिए सक्रिय हैं. इसके कारण व्यवस्था चरमरा गई है. दलालों की नीचे से ऊपर तक पहुंच हैं. बीमारियों के चलते आजकल हर प्रकार की जांचों के लिए भी कोई निश्चित दाम तय नहीं है. वर्तमान समय में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल लखनऊ में डेंगू व संबंधित बीमारी से प्रभावित पीड़ितों की संख्या साढ़े चार हजार पार कर चुकी है. मरीज मर रहे हैं, लेकिन अधिकारी किसी भी मौत को मानने से इंकार कर रहे हैं. स्वास्थ्य महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार सरकारी अस्पतालों व प्रयोगशालाओं में डेंगू के 4525 मामले सामने आ चुके हैं. इसके विपरीत सरकारी आंकड़ों में दावा है कि केवल 5 मौतें ही हुई हैं. जबकि मीडिया रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरुण सिन्हा का कहना है कि डेंगू के मामलों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. निजी अस्पतालों व पैथोलाजी लैब से पूरी जानकारी लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. डेंगू से प्रभावित इलाकों की डिजिटल मैंपिंग कराने का भी फैसला हुआ है. लेकिन यह तो केवल सरकारी शब्दावलियां हैं. असलियत यह है कि रोगी इलाज के अभाव में मर रहे हैं. डेंगू से मरने वालो की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. अधिकारीगण सरकार को आंकड़ों का खेल पेश कर गुमराह कर रहे हैं. आज अस्पतालों की हालत यह हो रही है कि लाइन में खड़े होने व पर्चे बनवाने से लेकर दवाइयों की लाइन में लगने तक मारपीट व हंगामा तक हो रहा है. लोहिया अस्पताल में तो महिलाओं से चेन लूटने तक की वारदातें हो चुकी हैं. अस्पतालों में मरीजों व तीमारदारों की सुरक्षा ताक पर है. अस्पतालों में भारी भीड़ के चलते कहीं-कहीं पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता की वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है. जिसके कारण कई जगह परिजनों की ओर से हंगामा करने की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं. अस्पतालों में चिकित्सकों की ओर से लापरवाही की जा रही है. अभी लखनऊ के एक अस्पताल में एक लड़की का नाक का ऑपरेशन किया गया लेकिन चिकित्सक की लापरवाही के कारण बालिका की मौत हो गई. उक्त बालिका का केवल साइनस का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई. इस तरह के माहौल में प्रदेश के लोग जीने के लिए अभिशप्त हैं. अस्पतालों का आलम यह है कि कोई मरीज फर्श पर ही तड़प रहा है तो किसी बच्चे को गोद में लेकर ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है. मरीजों के दबाव की वजह से अस्पतालों की इमरजेंसी में भर्ती तक ठप्प हो रही है. लोहिया अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में ओपीडी व बरामदे में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है. वहीं सिविल अस्पताल आदि में कर्मचारियों के कार्य-बहिष्कार के चलते हालात दयनीय है. जो मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही.

डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के साथ तेज बुखार के कारण राजधानी लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के कई शहरों की जनता व्यवस्था के कारण नाराज है. सफाई व्यवस्था और फॉगिंग का बुरा हाल है. मशीनों की खराबी के कारण अधिकतर जगहों पर फॉगिंग नहीं हो पा रही है. फॉगिंग हो भी रही है तो नेताओं और नौकरशाहों की कॉलोनियों में. राजधानी लखनऊ समेत प्रदेशभर में फैल रही गंदगी के कारण ही खतरनाक रोग पनप रहे हैं. फिर भी सफाई व्यवस्था चौपट है. कई जगह सफाई कर्मचारियों के साथ आम लोगों की हिंसक झड़पें हो रही हैं. विडंबना यह है कि इसी में प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा कर ही है और अखबारों और चैनेलों पर विज्ञापन के माध्यम से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पॉश इलाक़ों में 'सरकारी डेंगू' का प्रकोप अधिक

डेंगू बुखार के कारण सबसे अधिक मौतें जन-सुविधाओं के लिए तरसने वाले इलाकों में हो रही हैं. लेकिन हड़कंप खास लोगों में अधिक है. उसी आम और खास के फर्क से सरकारी आंकड़े भी तैयार किए जा रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू का सबसे अधिक प्रभाव लखनऊ के पॉश इलाकों में है. राजधानी में डेंगू के करीब 16 प्रतिशत मरीज अकेले गोमतीनगर में हैं, जबकि इंदिरा-नगर में करीब 9 प्रतिशत मरीज हैं. यह ब्यौरा सिर्फ उन मरीजों का है, जिनकी सरकारी पैथॉलजी में एलाइजा की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. निजी अस्पतालों में भर्ती 90 फीसदी घोषित डेंगू मरीजों का आंकड़ा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है.

राजधानी के सरकारी अस्पतालों ने एक जनवरी से 21 सितंबर तक का ब्यौरा तैयार किया था. इन नौ महीनों में एलाइजा जांच के बाद सिर्फ 346 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई. सबसे ज्यादा मरीज उन इलाकों से हैं, जो तुलनात्मक रूप से काफी पॉश और साफ-सुथरे माने जाते हैं. गोमती नगर और इंदिरानगर के बाद सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज राजाजीपुरम, आलमबाग, अलीगंज, जानकीपुरम और कानपुर रोड के हैं. शहर से बाहर मोहनलालगंज और गोसाईगंज में सबसे अधिक मरीजों में एलाइजा टेस्ट के बाद डेंगू की पुष्टि हुई. पॉश इलाकों में डेंगू पर सफाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अफसर कहते हैं कि विकसित और पॉश कॉलोनियों में बड़े-बड़े बंगले हैं. इनमें से ज्यादातर खाली पड़े हैं. बरसात का पानी इनकी छतों और छज्जों पर जमा रहता है. इसे साफ करने वाला कोई नहीं. कई लोगों ने मकान किराए पर दे रखे हैं. किराएदार सफाई के प्रति ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते. इससे वहां जमा साफ पानी डेंगू मच्छर के प्रजनन के लिए मुफीद होता है. दवा का छिड़काव करने वाले कर्मचारियों को भी इन मकानों के भीतर नहीं जाने दिया जाता. लखनऊ के सबसे समृद्ध और पॉश गोमती नगर की आबादी करीब नौ लाख है. शहर और इसके आसपास की आबादी करीब 45 लाख है. आबादी के इस आंकड़े के हिसाब से गोमती नगर की आबादी कुल आबादी का 20 प्रतिशत है, जबकि डेंगू के कुल मरीजों की 25 फीसदी संख्या यहीं है.

डेंगू प्रभावित इलाक़े

इलाका	आबादी	मरीज
गोमती नगर	नौ लाख	57
इंदिरानगर	1.22 लाख	31
मोहनलालगंज	20 हजार	19
फैजुल्लागंज/जानकीपुरम	1.60 लाख	21
तेलीबाग	65 हजार	15
अलीगंज	60 हजार	14
चिनहट	42 हजार	13
आलमबाग	1.20 लाख	13
कानपुर रोड	80 हजार	11
चौक	85 हजार	10
राजाजीपुरम	70 हजार	10

समाजवादी पार्टी पर शिवपाल का आधिपत्य, अखिलेश यादव और उनकी टीम बाहर

अब तुरुप के इक्के पर नज़र

- दागियों विवादियों की समाजवादी पार्टी में होने लगी धड़ाधड़ इंट्री
- क़ौमी एकता दल का विलय हुआ, अमनमणि को टिकट मिला
- अखिलेश ने अधिकार छोड़े, पार्टी ऑफिस भी जाना छोड़ दिया

प्रभात रंजन दीन

आखिरकार क़ौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो ही गया. इस विलय में नैतिकता भी विलीन हो गई. कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और उसके भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विरोध सुर्ख़ियों में रहा है. इस मसले पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच ऐसी तनातनी बढ़ी कि समाजवादी पार्टी बिखराव के मुहाने पर आ गई. विडंबना यह है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी नैतिकता के स्टैंड पर कायम अपने बेटे अखिलेश का साथ नहीं दिया. मुलायम ने भी यह साबित किया कि राजनीति की प्राथमिकताओं में नैतिकता कहीं नहीं ठहरती. छह अक्टूबर को कौमी एकता दल के सपा में विलय का प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने औपचारिक ऐलान किया, लेकिन यह अंदाजा चार अक्टूबर से ही लगने लगा था, जब शिवपाल ने कुख्यात अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को विधानसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की थी. उसी दिन जब अखिलेश ने कहा कि उन्होंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए हैं और उनके हाथ में तुरुप का पत्ता है, जिसे वे ऐन समय पर फेकेंगे, तो परिपक्व नेताओं ने कहा कि मुख्तार अंसारी का पार्टी में आना और पार्टी का टूटना तय हो गया है. शिवपाल ने जो 81 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है उससे भी यही संकेत दिया है, क्योंकि कार्यकारिणी में अखिलेश यादव भी नहीं हैं और उनकी टीम के सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है.

> मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी को ताक पर रखते हुए माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय का छह अक्टूबर को ऐलान कर दिया गया.सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मीडिया को बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की अनुमति के बाद कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है.

बहरहाल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी को ताक पर रखते हुए माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय का छह अक्टूबर को ऐलान कर दिया गया.सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मीडिया को बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की अनुमति के बाद कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है. शिवपाल ने यह भी जोड़ा कि अखिलेश यादव की भी इसमें सहमति थी. जबकि अखिलेश की तरफ से सहमति का कोई बयान जारी नहीं हुआ है. इस मसले पर उनकी नाराजगी तो उसी समय सार्वजनिक हो गई थी, जब उन्होंने बलराम यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था. अखिलेश यादव ने तब साफ-साफ कहा था कि वे पार्टी में किसी दागी चेहरे का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करेंगे. अखिलेश की इस नाराजगी के बाद मुलायम सिंह यादव ने 28 जून को लखनऊ में संसदीय बोर्ड की बैठक बुला कर कौमी एकता दल के विलय के फैसले को निरस्त कर दिया था. तभी बलराम यादव की दोबारा कैबिनेट में वापसी हो सकी थी.

शिवपाल के मुताबिक समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विलय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सीधे निर्देश से हुआ है. उनके फैसले के बाद कौमी एकता दल का सपा में बाकायदा और औपचारिक तौर पर विलय हो चुका है. पिछली बार भी शिवपाल यादव ने यही कहा था कि नेताजी के निर्देश पर कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ है.

अब बदली हुई स्थितियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को प्रतीक्षा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है, जिसे वे ऐन मौके पर फेकेंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी यह बताता है कि सपा के अंदर का विवाद कितना गहरा गया है. अखिलेश शिवपाल की भिड़ंत अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि पार्टी को दो भागों में बांटने वाली विभाजन रेखा स्पष्ट तौर पर दिखने लगी है. टिकट के बंटवारे पर नए प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल की मनमानी देखते हुए मुख्यमंत्री यह बोल चुके कि उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुरुप का पत्ता उनके पास है, जो समय आने पर फेंका जाएगा. अब लोगों का ध्यान अखिलेश के तुरुप के पत्ते पर लगा हुआ है और इसे लेकर तमाम कयासबाजियां चल रही हैं.

बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड में सपत्नीक आजीवन कारावास की सजा काट रहे सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर शिवपाल ने एक बार फिर अखिलेश की नाराजगी को उकसाया. शिवपाल ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को भी टिकट दे दिया है. अमनमणि पर उसकी पत्नी सारा की हत्या का आरोप है, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है. अमनमणि को टिकट दिए जाने के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है. सपा ने अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि को नौतनवा विधानसभा से टिकट दिया है. अमरमणि त्रिपाठी चार बार विधायक रह चुके हैं. अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि जिसके खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, समाजवादी पार्टी ने उसी को टिकट कैसे दे दिया? अखिलेश ने कहा कि उन्होंने टिकट बंटवारे के सभी अधिकार छोड़ दिए हैं. सवालों की बौछार पर अखिलेश ने पत्रकारों से ही पूछा, आप क्या चाहते हैं, मैं ईमानदार उत्तर दूं या नेताओं वाला जवाब दूं? अखिलेश बोले, 'टिकट बंटवारा पार्टी के अंदर की बात है. हमारी राय आप जानते हैं. मैं अपनी कुछ आदतें बदल ही नहीं सकता. मुझे जानकारी नहीं है.' टिकट बंटवारे पर जब उनसे पूछा गया कि टिकट बंटवारे में क्या उनकी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो अखिलेश ने ताश के खेल का जिक्र करते हुए कहा कि अंत में जीत उसी की होती है जिसके पास तुरुप का इक्का होता है. अखिलेश ने चुनौती उछालने के अंदाज में कहा, विधानसभा चुनाव में अभी समय शेष है, देखिए आखिर में क्या होता है.

> अखिलेश-शिवपाल का तनावपूर्ण रिश्ता तब संगठनात्मक शक्ल ले गया, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का पक्ष लेना शुरू कर दिया. कौमी एकता दल के सपा में विलय के विवाद से शुरू हुआ यह प्रकरण अखिलेश के सपा अध्यक्ष पद से निष्कासन, शिवपाल के महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय विभाग की कटौती और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट मंत्रियों की बर्ख़ास्तगी और मुख्य सचिव दीपक सिंघल की रुख़सती के मुकाम तक आ पहुंचा.

अखिलेश-शिवपाल का तनावपूर्ण रिश्ता तब संगठनात्मक शक्ल ले गया, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का पक्ष लेना शुरू कर दिया. कौमी एकता दल के सपा में विलय के विवाद से शुरू हुआ यह प्रकरण अखिलेश के सपा अध्यक्ष पद से निष्कासन, शिवपाल के महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय विभाग की कटौती और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट मंत्रियों की बर्खास्तगी और मुख्य सचिव दीपक सिंघल की रुख्सती के मुकाम तक आ पहुंचा. मुलायम के सीधे हस्तक्षेप से बर्खास्त मंत्रियों की वापसी तो हो गई लेकिन अखिलेश की सपा अध्यक्ष की कुर्सी वापस नहीं मिली और शिवपाल से छीने गए महत्वपूर्ण विभाग वापस नहीं मिले. अब मामला टिकट बंटवारे की मनमानी और अखिलेश के तुरुप के पत्ते के खुलने की प्रतीक्षा पर आकर टिक गया है.

अखिलेश का यह कहना कि उन्होंने टिकट वितरण पर अपना सुझाव देना छोड़ दिया है. काफी कुछ संकेत दे रहा है. नए सचिवालय के उद्घाटन के मौके पर जब वे मीडिया से मुखातिब थे तो वे बुझे-बुझे से थे और उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा था. अखिलेश ने कहा कि किसे टिकट दिया जाए या किसे पार्टी में शामिल कराया जाए, इस बारे में उनके क्या विचार हैं, यह सबको मालूम है. अखिलेश ने फिर कहा कि ताश के खेल में अंततः तुरुप का इक्का ही जीतता है. देखिए, आगे-आगे होता क्या है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिवपाल ने बना डाली अपनी टीम, अखिलेश बाहर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नई टीम गठित कर डाली. शिंवपाल यादव ने अपने 81 खास सिपहसालारों की टीम घोषित की है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके समर्थक इस टीम में शामिल नहीं हैं. सपा की प्रदेश कार्यकारिणी साफ तौर पर शिवपाल-टीम है, जिसमें ओमप्रकाश सिंह, किरनपाल सिंह, रघुनंदन सिंह काका, उदय राज यादव, श्रीपति सिंह समेत कई खास लोग शामिल हैं. शिवपाल ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी भी अखिलेश से सलाह लेकर बनाई गई है. शिवपाल की टीम में ओमप्रकाश सिंह को सपा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है. किरनपाल सिंह को सपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. राजकुमार मिश्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. रघुनंदन सिंह काका, विधायक उदयराज यादव, श्रीपति सिंह, बख्तावर सिंह, अनूप गुप्ता, एसएन सिंह, सत्येंद्र उपाध्याय, राजेश यादव, पीएन चौहान, संतोष द्विवेदी, विद्यावती राजभर, श्यामलाल पाल, रामदुलार राजभर, सुरेश शुक्ला, अशोक पटेल, प्रेम प्रकाश वर्मा, संत सिंह सेरसा, राहुल कौशिक, देवेंद्र सिंह, रंजना सिंह, पारुल दीक्षित और दीपक मिश्र को सचिव बनाया गया है. सदस्यों की फेहरिस्त में अंबिका चौधरी, नारद राय, राजेंद्र चौधरी, एसआरएस यादव, धनंजय उपाध्याय, उज्जवल रमण सिंह समेत अन्य नेता शामिल हैं. इस लिस्ट में मुलायमवादी बुद्धिजीवी डॉ. अशोक वाजपेयी का नाम शामिल नहीं है. ■

सपा का समानान्तर मुख्यालय! संकेत अच्छे नहीं हैं

समाजवादी पार्टी का एक समानान्तर मुख्यालय भी तैयार है, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके समर्थकों का कुनबा बैठ रहा है. दो धारा साफ-साफ बहती दिख रही है. विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी का मुख्यालय अब शिवपाल और उनके समर्थकों के कब्जे में है तो बंदरियाबाग स्थित जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट अखिलेश और उनके समर्थकों का मुख्यालय बन गया है. पार्टी के ही लोग इन दो दफ्तरों को समाजवादी पार्टी का दो समानान्तर मुख्यालय बता रहे हैं. जिस तरह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संगठनात्मक तौर पर कमजोर करने की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह अखिलेश के निराशा भरे बयान आ रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर अच्छे संकेत नहीं हैं. अखिलेश ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय जाना छोड़ दिया है. अब वे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट को अपने संगठनात्मक कार्यकलापों के लिए दफ्तर बना रहे हैं. सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश समर्थक नेताओं को पार्टी के दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पार्टी दफ्तर में उनके बैठने के कमरों को भी खाली करा लिया गया. इस तरह का व्यवहार देखते हुए ही अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट को अपना नया दफ्तर बनाने का फैसला लिया. लखनऊ में सात नंबर बंदरियाबाग वाला बंगला अब अखिलेश यादव का नया चुनावी दफ्तर है. इसी दफ्तर से जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का भी संचालन हो रहा है. अखिलेश यादव ही ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं. राजेंद्र चौधरी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें शिवपाल ने अपनी कार्यकारिणी में सदस्य की हैसियत दी है. चौधरी ने भी पार्टी मुख्यालय जाना बंद कर दिया है. पार्टी के नेता कहते हैं कि अखिलेश के साथ-साथ वे सारे नेता भी ट्रस्ट को ही अपना केंद्र बना रहे हैं, जिन्हें शिवपाल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है. अखिलेश के इन साथियों में सुनील यादव, संजय लाठर, आनंद भदौरिया, नईमुल हसन, अतुल प्रधान, मोहम्मद एबाद, बृजेश यादव, गौरव दुबे, दिग्विजय सिंह, सौरभ यादव वगैरह शामिल हैं. पार्टी के ही युवा नेता ट्रस्ट के दफ्तर को पार्टी का समानान्तर मुख्यालय भी बताने लगे हैं. पार्टी में मचे घमासान के बीच बड़े नेता व राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव अखिलेश का खुला साथ दे रहे हैं. सांसद धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव भी अखिलेश के साथ खड़े हैं. ■

साहित्य अकादमी चुनाव की बिसात

अनंत विजय

दो हजार चौदह के आम चुनाव के बाद देश में विचारधारा की लड़ाई ज्यादा तेज हो गई है. वामपंथ के कमजोर होने और दक्षिणपंथ के मजबूत होने से विचारधारा की इस लड़ाई का असर देश की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर दिखाई देने लगा है. सत्ता से करीबी का लाभ लेकर जिस तरह से वामपंथियों ने देशभर के कला, संस्कृति और साहित्यिक प्रष्ठिानों पर कब्जा जमाया हुआ था वहां से उनका बोरिया बिस्तर गोल होने लगा. इस बात को लेकर तमाम तरह का वितंडा खड़ा किया गया. एक तर्क ये दिया गया कि दक्षिणपंथियों के पास बुद्धिजीवियों की कमी है. यह सही हो सकता है, लेकिन वामपंथियों के किस तरह के बुद्धिजीवी हैं इसकी पड़ताल करने की जरूरत है. वहां तो ज्यादातर उसी तरह के बुद्धिजीवी हैं जो सत्ता की खाद से तैयार किए गए. उनको सत्ता और विचारधारा की सीढ़ी ने बड़ा बनाया. वामपंथ की एक खासियत तो ये रही है जिसके लिए उनको दाद देनी चाहिए. खासियत ये कि वो अपनी विचारधारा के लेखकों को बड़ा बनाते रहे हैं. लेखक चाहे औसत भी हो, उसकी रचना चाहे मामूली हो, लेकिन अगर वो मार्क्सवाद का ध्वजवाहक है और मजबूती से झंडा थाम कर साहित्य की दुनिया में चलने की ताकत रखता है, तो उसको बढ़ावा देने में पार्टी से लेकर कार्यकर्ता तक कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. ध्वज वाहकों की पताका के आकार पर लेखक का कद तय होने लगा. जिसकी जितनी बड़ी पताका वो उतना बड़ा लेखक. पताका के आकार के आधार पर उनके लेखन और उनकी कृतियों पर सेमिनार और पुरस्कार आदि तय होने लगे. उनका विरोध करने वालों की आवाज दबाई जाने लगी. ये बहुत लंबे समय तक चला. इस तरह से वामपंथियों ने अपनी विचारधारा के ध्वजवाहकों को बड़े लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया.

इस खेल में दक्षिणपंथी पिछड़ गए और अबतक पिछड़ते ही नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी विचारधारा के लेखकों को बड़ा बनाने का उपक्रम नहीं किया. लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की कई प्रदेशों में सरकारें रही हैं, लेकिन वहां से भी अनुदान से लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं में विज्ञापन से लेकर बड़े-बड़े पुरस्कार वामपंथियों या उस तरफ झुकाव रखने वालों को ही दिए जा रहे हैं. उनकी विचारधारा के लेखकों का न तो सम्मान हो पाया है और न ही उनको पुरस्कार आदि देने का उपक्रम. मजेदार तो ये होता है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों में भी भारत सरकार को जमकर कोसा जाता है. भारत सरकार की नीतियों को फासीवादी तक करार दिया जाता है. संस्कृति मंत्रालय से सहयोग प्राप्त ऐसे कार्यक्रमों में कोसा तो मंत्रालय को भी जाता है लेकिन इस ओर अब तक भारत सरकार का ध्यान नहीं जा पाया है या अफसरशाही पर उनका नियंत्रण नहीं है जो बगैर जांचे अनुदान आदि देने का फैसला कर लेते हैं. यह बेहद मनोरंजक स्थिति है कि पैसे देकर फासीवादी सरकार का आरोप लगवाना. खैर ये अवांतर प्रसंग है जिसपर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

फिलहाल हम बात कर रहे थे साहित्यक संस्थाओं की. पुरस्कार वापसी के वक्त से चर्चा में आई साहित्यकारों की संस्था साहित्य अकादमी पर कब्जे को लेकर वामपंथी लेखकों ने कमर कस ली है. साहित्य अकादमी की मौजूदा

जनरल काउंसिल का लगभग एक साल बचा है, लेकिन अगले अध्यक्ष को लेकर वाम खेमे में तैयारियां शुरू हो गई हैं. अगले साल अक्टूबर में होने वाली नई आमसभा के गठन और उसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मौजूदा उपाध्यक्ष और कन्नड़ के लेखक कंबार के नाम पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन उनकी लेखकों के बीच स्वीकार्यता संदिग्ध है. उनकी सबसे बड़ी कमजोरी या उनकी राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उनकी भाषा और उनकी संवाद करने की क्षमता को लेकर है. उनको लेकर किसी भी खेमे में कोई खास उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है. अगले आमसभा के चुनाव में मौजूदा आमसभा के सदस्यों की अहम भूमिका होती है लिहाजा मौजूदा अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी के कदमों पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं. चर्चा तो ये भी है कि विश्वनाथ तिवारी दूसरे कार्यकाल के लिए भी प्रयास कर सकते हैं. दरअसल साहित्य अकादमी के संविधान में दो बार अध्यक्ष बनने पर कोई रोक नहीं है. जानकारों का मानना है कि इसी के मद्देनजर तिवारी जी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं. विश्वनाथ तिवारी हिंदी भाषा से बनने वाले पहले अध्यक्ष हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया जाए तो. इसके पहले हिंदी का कोई लेखक साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नहीं बन पाया था. अत्यंत मृदुभाषी विश्वनाथ तिवारी को सभी भाषाओं के लेखकों का विश्वास भी हासिल है. पुरस्कार वापसी के वक्त जिस तरह से विश्वनाथ तिवारी ने उस मुहिम को हैंडल किया उसको लेकर भी सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग तिवारी जी से खुश बताए जाते हैं. अब ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि विश्वनाथ तिवारी की क्या इच्छा है और वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं.

साहित्य अकादमी पर कब्जे की जंग इस बार काफी दिलचस्प होगी. पुरस्कार वापसी के वक्त से लेकर अबतक अशोक वाजपेयी ने खुद को वामपंथी या कहें कि तथाकथित वृहत्तर सेक्युलर लेखकों का अगुवा बनने में कामयाबी हासिल कर ली है. यह कितनी बड़ी बिडंबना है कि जिस अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद के चुनाव में वामपंथियों ने एकजुट होकर हरवा दिया था, वही वामपंथी इन दिनों अशोक वाजपेयी को अपना नेता मान रहे हैं. ये वही अशोक वाजपेयी हैं जिनको वामपंथियों ने कलावादी कहकर साहित्य से खारिज करने की भरपूर कोशिश की थी. ये तो अशोक जी प्रतिभा और उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव था कि उन्होंने वामपंथियों को अप्रसांगिक कर दिया. संभव है ये अशोक वापजेयी की कांग्रेस के नेताओं की संगति का असर हो. अगर आप देखें तो कांग्रेस ने वामपंथियों को सत्ता का लॉलीपॉप देकर बिल्कुल अप्रसांगिक कर दिया था. 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वामपंथी हाशिए पर चले गए थे. दरअसल, कांग्रेस ने वामपंथी लेखकों और विचारकों को संस्थाओं और अकादमियों की कुर्सी से लेकर विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का अधिकार देकर उनके तेवरों को कुंद कर दिया. ये कांग्रेस की रणनीति का ही हिस्सा था कि वामपंथी सत्ता प्रतिष्ठानों से जुड़कर अपने आप को सुविधाभोगी बनाते चले गए और संघर्ष और विरोध का उनका माद्दा खत्म होता चला गया. ये तो भला हो जेएनयू प्रकरण का जिसने एक बार फिर से वामपंथियों को मंच से लेकर मौका तक मुहैया करवा दिया.

अगले साल होने वाला साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प होगा. साहित्य अकादमी के संविधान के मुताबिक उसकी जनरल काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा, विश्वविद्यालायों के नुमाइंदे और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं. इस वक्त देश में ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यह माना जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सजग रहे तो उन राज्यों से उनकी विचारधारा के लोगों के ही नामों का पैनल भेजा जाएगा. यही स्थिति विश्वविद्यालयों की भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में वामपंथियों को दिक्कत हो सकती है और साहित्य अकादमी के उनके हाथ से निकलने का खतरा पैदा हो सकता है. अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग असावधान रहे और उनके शासन वाले राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यों के पैनल में वामपंथियों का नाम आ गया तो फिर वो हाथ मलते रह जाएंगे. जिस तरह से वाम खेमा अभी से साहित्य अकादमी के चुनाव को लेकर सजग हो गया है उससे इस बात की संभावना प्रबल है कि साहित्य अकादमी अध्यक्ष के चुनाव में कुछ न कुछ गुल खिलेगा. साहित्य अकादमी के पिछले चार पांच चुनाव से पूर्व अध्यक्ष गोपीचंद नारंग की भूमिका भी अहम रहती आई है और वो बड़े रणनीतिकार माने जाते रहे हैं. हर गुट और विचारधारा में उनके समर्थक रहे हैं और वो उसी तरह से अपनी चालें भी चलते रहे हैं. गोपीचंद नारंग ने मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी को परास्त किया था. उस वक्त भी अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह आदि ने हाथ मिला लिया था, लेकिन नारंग के आगे उनकी एक नहीं चली थी. इस बार गोपीचंद नारंग की तबीयत नासाज होने की वजह से संभव है कि वो उतने सक्रिय नहीं रह पाएं. साहित्य अकादमी पर कब्जे को लेकर जिस तरह से बिसाते बिछने लगी हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि विचारधारा विशेष के लेखक इस संस्था पर कब्जे को लेकर कितने बेचैन हैं कि बारह महीने पहले से ही रणनीति पर काम शुरू हो गया है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

अपने रहमतल्लिल आलमीन को जानिए

मुहम्मद साहब की जीवनी पर एक नई किताब

इतिहास की मशहूर हस्तियों का पैग़म्बर-ए-इस्लाम के बारे में ज़िक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मानना था कि दुनिया के हर व्यक्ति को इस्लाम के विचारों का अनुसरण करना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि मैं हज़रत मुहम्मद की इज्ज़त करता हूं कि उन्होंने बिखरे हुए समाज को एकजुट किया और कुरान को मैं सिर्फ मुस्लमानों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के सभी धर्मों के लोगों के लिए मार्गदर्शक मानता हूं.

वसीम अहमद

पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद साहब के जीवनी पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं. लेकिन इस विषय पर एक ऐसी किताब की जरूरत महसूस की जा रही थी जो मौजूदा दौर की समस्याओं की पृष्ठभूमि में सीरत-ए-नबवी (मुहम्मद साहब की जीवनी) को पेश कर सके. मोहम्मद तशकील कैफी की किताब 'नो योर रहमतल्लिल आलमीन' इस कमी को पूरा करती नज़र आती है. किताब में कुल आठ अध्याय हैं. पहले अध्याय में पैगंबर साहब की जिंदगी के बारे में विस्तार से रोशनी डाली गयी है. दूसरे अध्याय में बताया गया है कि मुहम्मद साहब के बारे में कुरान, हिंदू धार्मिक ग्रंथ और बाइबिल क्या कहते हैं. तीसरे अध्याय में जिहाद की हकीकत बयान की गई है. चौथे अध्याय में इस्लाम में महिलाओं के अधिकार और उनकी हैसियत पर रोशनी डाली गयी है. पांचवें अध्याय में पैग़म्बर साहब की भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है. छठे अध्याय में सुप्रसिद्ध गैर-मुस्लिमों के मुहम्मद साहब के बारे ख्यालत का जिक्र है. जबकि सातवें अध्याय में कुरान और पर्यावरण के बारे में बताया गया है और आखिरी अध्याय में हजतुल्लविदा के मौके पर दिए गये खुतबे की अहमियत की विवेचना की गयी है.

किताब में इस्लाम से संबंधित प्रचलित गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की गई है. लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि पैग़म्बर मुहम्मद साहब किसी क्षेत्र विशेष किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन पूरी मानवता के लिए उदाहरण था. इस संबंध में एक अहम सवाल कि पैग़म्बर तमाम मानव जाति के लिए शांति और सुरक्षा के संदेश लेकर आए थे तो फिर उन्होंने जंगें क्यों लड़ीं. इस सवाल के जवाब में कैफी ने यह साबित किया है कि वो सारी जंगें आत्मरक्षा में थीं जो निरंकुश ताकतों और भ्रष्ट व्यवस्था के ख़िलाफ़ थी. यही वजह है कि जंग के दौरान मुसलमानों के लिए कुछ शर्तें तय थीं, जिसकी परिधि में रहते हुए ही जिहाद की इजाज़त थी, जैसे प्रसिद्धि और दौलत के लिए, जात बिरादरी के नाम पर और धार्मिक मतभेद की वजह से जंग न लड़ी जाए. उसी तरह इस बात को सख्ती से रोका गया कि किसी भी हालत में महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और ज़ख्मियों पर हाथ न उठाया जाए और दुश्मन फौजों को जलील न किया जाए और न ही उनके शरीर के किसी अंग को काटा जाए.

जिहाद का मतलब साफ करते हुए कैफी लिखते हैं कि जिहाद का अर्थ धमाका करना, धर्म के नाम पर खून बहाना या आतंकवाद फैलाना नहीं, बल्कि कुरान और पैग़म्बर-ए-इस्लाम के मुताबिक जिहाद अपनी आत्मा को पवित्र करने और मानव जाति को मानवता सिखाने और उन तक इस्लाम का पैग़ाम पहुंचाने का नाम है. इतिहास की मशहूर हस्तियों का पैग़म्बर-ए-इस्लाम के बारे में ज़िक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मानना था कि दुनिया के हर व्यक्ति को इस्लाम के विचारों का अनुसरण करना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि मैं हज़रत मुहम्मद की इज्जत करता हूं कि उन्होंने बिखरे हुए समाज को एकजुट किया और कुरान को मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के सभी धर्मों के लोगों के लिए मार्गदर्शक मानता हूं. इसके अतिरिक्त लेखक ने हज़रत मुहम्मद साहब के संबंध में प्रोफेसर विलियम डब्लू हेए समेत दुनिया के कई दार्शनिकों, लेखकों, राजनेताओं आदि के दिए गये कथनों को उनके ब्लैक एंड व्हाईट फोटो के साथ छापा है.

कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि यह किताब जहां अपनी विषय वस्तु की वजह से महत्वपूर्ण है, वहीं इसकी बेहतरीन गेटअप और छपाई पाठक को सहज रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और आठ अध्याय पर आधारित यह किताब इस्लाम से संबंधित मौजूदा बहस में एक इज़ाफे की हैसियत रखती है. ■

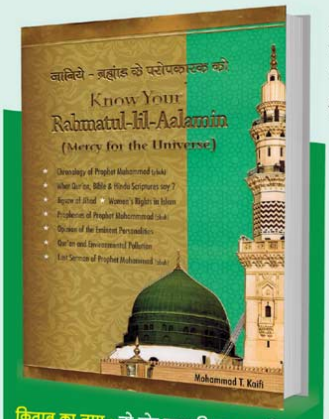

किताब का नाम : नो योर रहमतल्लिल आलमीन (अपने रहमतल्लिल आलमीन को जानिए)
लेखक : मोहम्मद तश्कील कैफ़ी
मुल्य : दर्ज नहीं

feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

साईं-साहित्य के कुछ आधार

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

शिरडी में बाबा के प्रवास-काल (लगभग 1860-1918 ई.) में महाराष्ट्र में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं की संख्या बहुत कम थी. इन समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस काल में इनमें शायद ही बाबा का नाम छपता हो. 1918 ई. में बाबा के देह-त्याग के उपरान्त 'श्री शिरडी साईं बाबा संस्थान' की ओर से 'श्री साई लीला' नामक एक औपचारिक प्रत्रिका प्रकाशित हुई, जो आज तक भी प्रकाशित हो रही है. दासगणु, चांदोरकर, काकासाहेब दीक्षित एवं अन्य बहुत से भक्त जिनके माध्यम से बाबा के नाम का प्रसार हो रहा था, सदैव बाबा के विषय में कुछ भी कहने अथवा लिखने में अत्यधिक सत्यता एवं सतर्कता बरतते थे. 'साई प्रभा' (1915-1919) तथा 'श्री साई लीला' (1923 ई. से आज तक) नाम की प्रकाशित दोनों ही पत्रिकाओं के पीछे प्रकाशक, संपादक अथवा लेखक में से किसी का भी कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था. बाबा के प्रति केवल शुद्ध भक्ति-भाव से प्रेरित होकर उन्होंने इन पत्रिकाओं में बाबा से सम्बन्धित अनुभव लिखे थे, ताकि अन्य भक्त भी उनसे लाभान्वित हों. बाबा से सम्बन्धित दिव्य लीलाओं एवं घटनाओं के संदर्भ में अन्य लोगों को जानकारी देते समय उन्होंने कभी भी बढ़ा-चढ़ाकर मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा और न ही बाबा के सान्निध्य में रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने कपोलकल्पित चमत्कारों के विषय में नहीं लिखा.

आज बाबा की महासमाधि के दशकों बाद भी उनका नाम भारत और विदेशों में निरंतर दूर-दूर तक फैल रहा है. जैसे कि बाबा ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी, शिरडी में आजकल भारत और विदेशों से आने वाले लाखों भक्तों का तांता लगा है और जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. भारत और विदेशों में बाबा के नाम पर सैकड़ों मंदिरों का निर्माण हुआ है. बाबा के नाम से विभिन्न भाषाओं के चलचित्रों, टीवी धारावाहिकों, पत्रिकाओं, ऑडियो-वीडियो कैसेट आदि की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें सूचीबद्ध करना सहज नहीं है. बाबा के जीवन पर आधारित कथाओं, समाचार, भक्तों के अनुभव संबंधी चर्चाओं, आज के साईं-आंदोलन के बहुमुखी आयाम और भक्तों के अनुभवों को ध्वनि/वीडियो एवं मुद्रण मीडिया के माध्यम से देखा जा सकता है. उनमें से कुछ अच्छे स्तर के हैं. परन्तु कभी-कभी उनमें बाबा के दिव्य व्यक्तित्व का चित्रण सच्चे और सही रूप में नहीं किया गया है. कुछ लोग इस सत्यता से परिचित नहीं हैं कि बाबा जैसे सद्गुरु को अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है. मात्र अपनी इच्छा से अपनी सूक्ष्म अलौकिक शक्तियों द्वारा सद्गुरु किसी भी जीवात्मा को कितनी दूर से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. सच्चा भक्त जिसे बाबा पर पूर्ण विश्वास है, वह कभी भी मनगढ़ंत और चमत्कारिक कथाओं के माध्यम से बाबा को इस रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा जो कि सत्यता के परे हो. ऐसी प्रस्तुतियां भक्तों में गलत संदेश पहुंचाती हैं और सद्गुरु, उनके दर्शन एवं शिक्षा-पद्धति को सही रूप से जानने में बाधक बनती हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

विश्व टेनिस में जलवा लेकिन ओलम्पिक में नाकाम

जुबानी जंग की भेंट चढ़ा भारतीय टेनिस

पसंद और नापसंद के चक्कर में नहीं मिलता पदक

बोपन्ना के बाद अब सानिया ने साधा पेस पर निशाना

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारत में टेनिस को लेकर अब अलग उत्साह देखा जा सकता है. देश में कई खिलाड़ी भारत को विश्व टेनिस जगत में अलग पहचान दे रहे हैं. उनमें चाहे पेस हो या फिर सानिया मिर्जा. इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही देश का गौरव है लेकिन दोनों के बीच में अक्सर जुबानी जंग देखी जा सकती है. दरअसल भारतीय टेनिस खिलाड़ी ओलम्पिक छोड़ अन्य प्रतियोगिता में अपना जलवा दिखाते हैं पर ओलम्पिक में पदक के नाम पर एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते हैं. ओलम्पिक में हर बार भारत टेनिस में पदक की आस लगाता है. यही आस बाद में धूमिल हो जाती है. हाल के दिनों में भारतीय टेनिस खिलाड़ी आपस में एक-दूसरों पर ताने कसते दिख रहे हैं. डेविस कप के दौरान पेस ने अपने साथी खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद बोपन्ना व सानिया मिर्जा ने पलटवार करते हुए कहां कि पेस केवल खबरों में रहने के लिए ऐसा करते हैं. इसी विवाद के चलते भारत को डेविस कप में स्पेन के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा. भारतीय टेनिस के इतिहास पर गौर किया जाये तो अभी तक इससे पूर्व इस तरह की जुबानी जंग पहले कभी देखने को नहीं मिली है. लंदन ओलम्पिक में भी पेस-भूपति के बीच आपसी मदभेद खुलकर सामने आया था. उस समय पेस के साथ जोड़ी बनाने को लेकर बोपन्ना और महेश भूपति ने साफ-साफ इन्कार कर दिया था. इसके बाद मामला तब और गरमाया जब पेस ने लंदन ओलम्पिक से हटने की धमकी दे डाली. खैर किसी तरह से मामला रफा-दफा हो गया, लेकिन उनके आपसी विवाद के चलते भारतीय टीम ओलम्पिक में कुछ नहीं कर सकी. रियो ओलम्पिक में भी इसी तरह की बयानबाजी हुई थी परिणाम सबके सामने हैं. ताजा मामला अब डेविस कप में सामने आया जब पेस ने रियो ओलम्पिक में नाकामी के बारे में कहा कि टीम का चयन सही नहीं किया गया था. उनका साफ इशारा अपने साथी खिलाड़ियों पर था. इसके बारे में वह आगे कहते हैं कि जो भी हुआ उससे भारत का नुकसान हुआ. पेस का भूपति के साथ पुराना विवाद रहा है. एक जमाने में वह दोनों एक साथ जोड़ी बनाकर खेलते थे लेकिन बाद में आपसी मनमुटाव के बाद अलग हो गये. हालांकि बीच में कई बार देश की खातिर एक साथ खेलने की बात कही जा रही थी. अब बोपन्ना ने भी पेस को खूब खरी-खोटी सुनाई है. दरअसल सारा खेल अपनी पसंद और नापसंद का है. पेस चाहते हैं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिले जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोपन्ना व सानिया पेस के साथ जोड़ी बनाने को लेकर मना कर चुके हैं. ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में पसंद और नापसंद के चक्कर में भारतीय टेनिस टीम की मिट्टी पलीद हो गई थी.

सवाल यह है कि देश के लिए पदक जीतना जरूरी है या फिर आपसी टकराव जरूरी है. खेलों में अक्सर भारतीय टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जैसी प्रतियोगिता में कमाल करते हैं लेकिन देश के खातिर कभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जरूरी नहीं समझते हैं. उन्हें लगता है ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में हाजरी लगा लेना बड़ी बात है. अब समय आ गया है कि भारतीय टेनिस संघ इस पर कोई कड़ा कदम उठाये नहीं तो ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में भारत को टेनिस में पदक नहीं मिल सकेगा.

भारतीय टेनिस इतिहास में कई जानदार खिलाड़ी आये हैं, लेकिन पेस और भूपति का नाम पूरे विश्व में अपने शानदार खेल के लिए चर्चा में रहा है. लेकिन विवाद का साथ भी खूब रहा है. दोनों का करियर काफी लम्बा रहा है. करीब 17 साल से दोनों ही टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन पेस ने कई मौकों पर भूपति से आगे प्रदर्शन किया है. एक जमाने में यह जोड़ी सुपर हिट मानी जाती थी. यह बात भी सत्य है कि भारतीय टेनिस में सबसे कामयाब जोड़ी है. कभी इस जोड़ी को सदाबहार जोड़ी के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसी जोड़ी को नजर लग गई और टूट भी गई. आरोपों का दौर भी जारी था. भूपति ने पेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पेस ने उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है. इस आरोप ने भारतीय खेल जगत में सनसनी फैला दी. दोनों के बीच जुबानी जंग ने भारतीय टेनिस को गर्त में धकेल दिया. आलम तो यह है कि दोनों का अहम देश के लिए नुकसानदेय साबित हुआ. जानकारों की माने तो दोनों 1994 में पहली बार एक साथ खेलने का फैसला किया. दोनों ने इस दौरान भारतीय टेनिस को शिखर पर पहुंचाया, लेकिन 2000 में उनके सम्बन्धों में पूरी तरह से दरार आ चुकी थी. इसके बाद कभी-कधार एक साथ खेले हैं, लेकिन वह कामयाबी नहीं मिल सकी जो पहले मिला करती थी. खैर भूपति और पेस की लड़ाई अब पुरानी हो चुकी है लेकिन उनके बाद के खिलाड़ियों से भी पेस के रिश्ते कोई खास नहीं रहे है. बोपन्ना और सानिया ने पेस के खिलाफ कई बार मोर्चा खोला है. डेविस कप टूर्नामेंट के दौरान जब पेस ने खुलेआम अपने साथी खिलाड़ियों पर तीखा प्रहार किया तो जवाब में सानिया और बोपन्ना ने उनके खिलाफ कई बातें कही. सानिया ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके दिल-दिमाग में जहर भरा हो जीतने का एक ही रास्ता है कि उसके साथ खेला ही न जाए. माना जा रहा है कि उनका यह ट्वीट पेस की ओर इशारा कर रहा है. इतना ही नहीं सानिया ने इससे पहले कहा था कि एक सुपर स्टार को खुश करने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है. देखा जाये तो सानिया अभी विश्व टेनिस में लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रही जबकि पेस करियर के अंतिम दौर में भी चरम पर है. दूसरी ओर बोपन्ना ने पेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह केवल खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाते रहे हैं. हालांकि कई मौकों पर बोपन्ना ने पेस की तारीफों का पुल भी बांधा है लेकिन, बाद में इस पर कई बार फजीयत भी हो चुकी है. बोपन्ना पेस के साथ जोड़ी बनाने से इन्कार करते आये हैं लेकिन उनका तर्क कोई ठोस नहीं रहा है. वह कहते हैं जीत के लिए सही विकल्प चुनना बेहद जरूरी है. उनकी नजर में पेस सही जोड़ीदार नहीं हैं.

सवाल यह है कि देश के लिए पदक जीतना जरूरी है या फिर आपसी टकराव जरूरी है. खेलों में अक्सर भारतीय टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जैसी प्रतियोगिता में कमाल करते हैं, लेकिन देश के खातिर कभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जरूरी नहीं समझते हैं. उन्हें लगता है ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में हाजरी लगा लेना बड़ी बात है. अब समय आ गया है कि भारतीय टेनिस संघ इस पर कोई कड़ा कदम उठाये नहीं तो ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में भारत को टेनिस में पदक नहीं मिल सकेगा. ■

भुवी की गेंदों में दिखी स्विंग

उत्तर प्रदेश के उभरते हुए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी शानदार स्विंग का लोहा मनवा रहे हैं. वन डे क्रिकेट में जलवा दिखाने वाले भुवी टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने वेस्टइंडीज और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. भुवनेश्वर कुमार ने वेस्टइंडीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में पांच विकेट झटक कर कीवियों के होश उड़ा दिये हैं. दरअसल भुवी इससे पूर्व वने डे क्रिकेट खेलते रहे हैं लेकिन चोट के चलते उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा था. इतना ही नहीं उनकी खराब फॉर्म को लेकर भी कई सवाल खड़ा किया जा चुका है. टीम में उनकी जगह भी बनती नहीं दिख रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वह पूरी तरह से लय में दिखे. उसके बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी गेंदों में पुरानी धार के साथ स्विंग भी देखने को मिली. भुवी ने हाल में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी. टेस्ट में उनका प्रदर्शन पहले उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हालांकि इस दौरान वह वन डे क्रिकेट में टीम इंडिया के सदस्य बने रहे.

यूपी के भुवनेश्वर कुमार मेरठ से ताल्लुक रखते हैं. मेरठ क्रिकेट के बल्ले के लिए

ख्याति प्राप्त है लेकिन भुवी यहां अपनी गेंदबाजी के लिए खूब सुर्खियों में हैं. भुवी को भारतीय क्रिकेट में तब पहचान मिली जब उन्होंने रणजी के रण में क्रिकेट के रिकॉर्ड पुरुष सचिन तेंदुलकर को जीरो पर चलता कर दिया था. साल 2009 रणजी ट्रॉफी में सचिन को आउट करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने रणजी स्तर पर अपनी अमीट छाप छोड़ी. इसके बाद टीम इंडिया में उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दिया था. यह वह दौर था जब भारतीय टीम में जहीर खान जैसे गेंदबाज अपने करियर के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके थे. 17 साल की आयु में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले भुवी ने जल्द ही टीम इंडिया में जगह पक्की कर ली. 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 में तीन विकेट झटकर क्रिकेट जगत में

भुवी को भारतीय क्रिकेट में तब पहचान मिली जब उन्होंने रणजी के रण में क्रिकेट के रिकॉर्ड पुरुष सचिन तेंदुलकर को जीरो पर चलता कर दिया था. साल 2009 रणजी ट्रॉफी में सचिन को आउट करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने रणजी स्तर पर अपनी अमीट छाप छोड़ी. इसके बाद टीम इंडिया में उन्होंने दस्तक देना शुरू कर दिया था. यह वह दौर था जब भारतीय टीम में जहीर खान जैसे गेंदबाज अपने करियर के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके थे.

सनसनी फैला दी थी. इसके बाद उनको वन डे क्रिकेट में आसानी से जगह मिल गई. 57 वन डे में 60 विकेट चटकाने वाले भुवी ने 13 टेस्ट में 35 विकेट चटकाये हैं. इससे पूर्व टीम से वह अंदर और बाहर होते रहे. खराब फिटनेस की मार भी उन पर पड़ी. आलम तो यह था कि डेब्यू मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले भुवी की गेंदों में एकाएक स्विंग और रफ्तार दोनों गायब होती दिखी. एक समय वह नई गेंद से विकेट निकालने वाले माही के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में सामने आये. दरअसल इससे पूर्व प्रवीण कुमार की गेंदबाजी की खूब चर्चा होती थी. प्रवीण कुमार ने भी करियर की शुरुआत में अपनी लाजवाब स्विंग के लिए जाने जाते थे. दोनों ही एक जगह से ताल्लुक रखते हैं लेकिन प्रवीण कुमार की खराब फिटनेस ने उन्हें टीम इंडिया से बेदखल कर दिया गया. ऐसा माना जाता है कि भुवनेश्वर कुमार के टीम में आने से प्रवीण कुमार के लिए टीम इंडिया में इंट्री के सारे दरवाजे बंद हो गये थे. कई मौकों पर भुवी की तुलना प्रवीण कुमार से की जाने लगी, लेकिन दोनों गेंदबाजों में फर्क देखा जा सकता है. भुवनेश्वर कुमार ने प्रवीण कुमार को हमेशा अपना आदर्श बताया है. भुवी के अनुसार हम दोनों का गेंदबाजी स्टाइल भी एक जैसा है. मैंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और रणजी ट्रॉफी में काफी देखा है. हालांकि यह बात सत्य है कि भुवी ने अपनी प्रतिभा के सहारे टीम इंडिया में जगह पक्की की. अब यह देखना रोचक होगा कि भुवी टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं. उनकी फॉर्म भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आने वालों दिनों में टीम इंडिया को कई सीरीज खेलनी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिवाय में नहीं है पाकिस्तानी अभिनेत्री

दिवाली पर अजय देवगन की फिल्म *शिवाय* प्रदर्शित हो रही है जिसका निर्देशन भी अजय देवगन ने ही किया है. फिल्म के ट्रेलर की खूब प्रशंसा हुई है और अजय के प्रशंसक बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा क़मर इस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रही हैं. जब इस बारे में *शिवाय* के अधिकृत पब्लिसिस्ट से बात की गई तो उन्होंने इसे नकार दिया. उनके अनुसार कोई भी पाकिस्तानी अभिनेता या अभिनेत्री *शिवाय* का हिस्सा नहीं है. निश्चित रूप से यह ख़बर मनगढ़ंत है.■

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे

अमिताभ-शत्रुघ्न साथ करेंगे फिल्म!

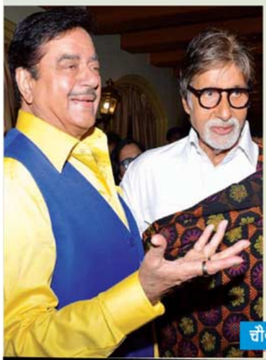

दोस्ताना, नसीब, काला पत्थर और शान जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साथ नज़र आए थे. इसके बाद दोनों के बीच संबंध ख़राब हो गए और फिर उन्होंने साथ में फिल्म नहीं की. हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक टॉक-शो के दौरान कहा कि अब दोनों के बीच संबंध बेहतर हैं, क्योंकि बीती बातों को उन्होंने भूला दिया है. जल्दी ही वे एक फिल्म भी साथ करने वाले हैं. थोड़े दिन में इस फिल्म के बारे में सभी को पता चल जाएगा.

फिल्म *काला पत्थर* की शूटिंग के दौरान अमिताभ और शत्रुघ्न के संबंध बिगड़ गए थे जिसका जिक्र कुछ किताबों में भी मिलता है. नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों में हाथपाई भी संभव थी. निर्देशक यश चोपड़ा ने किसी तरह यह फिल्म पूरी की.

जब अभिषेक की शादी में शत्रुघ्न को आमंत्रित नहीं किया गया, तो शत्रुघ्न ने अमिताभ द्वारा पहुंचाई गई मिठाई वापस कर दी थी. बाद में वे समय-समय पर अमिताभ पर हमले करते रहे. अब लग रहा है कि दोनों के बीच संबंध सामान्य हो गए हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सोनाली अब नहीं करेंगी गोरेपन को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन

अतीत में गोरेपन की क्रीम के विज्ञापनों में नज़र आ चुकीं अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अब त्वचा के रंग को लेकर पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने वाले उत्पादों का प्रचार करने वाली कंपनियों का ब्रांड एंबेसडर बनने की इच्छुक नहीं हैं. गौरतलब है कि *कॉमेडी नाइट्स बचाओ* शो में फिल्म *पार्च्ड* की अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी का सांवले रंग के कारण मजाक उड़ाया गया था. इस बारे में सोनाली ने कहा कि त्वचा के रंग को लेकर मजाक बनाना सरासर गलत है.

सोनाली ने कहा, मुझे लगता है कि किसी की त्वचा के रंग को लेकर मजाक करना बिल्कुल गलत है. हालांकि, मुझे इस बात की खुशी है कि हर कोई इन बातों के प्रति जागरूक हो रहा है. मैंने अपने करियर की शुरुआत में गोरेपन से संबंधित कुछ विज्ञापनों में काम किया है, अगर मुझे आज ऐसी पेशकश होती है, तो मैं गोरेपन वाले विज्ञापन नहीं करूंगी. सोनाली (41) इससे पहले इमामी नैचुरली फेयर का प्रचार कर चुकी हैं. इस बारे में अभिनेत्री ने कहा कि उस समय वह युवा थीं और उन्हें पैसे की जरूरत थी.■

सेल्फी की शौक़िन करीना कपूर

> मैं कभी भी योजना नहीं बनाती. मनीष मेरा भाई है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है. मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती जो दिल कहता है वो करती हूं. सिर्फ एक बार बचपन में मैंने फिल्मों का बड़ा सितारा बनने की बात सोची थी.

करीना कपूर खुद को सेल्फी क्वीन कहती हैं. सेल्फी लेने का उन्हें इतना शौक है कि प्रत्येक 5-10 मिनट में एक सेल्फी ले ही लेती हैं. यह बात करीना ने एक टीवी शो में कही, जिसमें उनके साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी थे जो करीना के अच्छे दोस्त हैं.

शो की होस्ट कमल सिद्धू ने करीना से पूछा कि मोबाइल फोन के जरिये उन्होंने आखिरी फोटो किसका लिया है, तो करीना ने कहा मैं सेल्फी क्वीन हूं. इस कारण मैंने अपना ही फोटो लिया होगा. वैसे भी मैं प्रत्येक 5-10 मिनट में सेल्फी लेती हूं.

इस शो में करीना ने अपने बारे में एक और ख़ास बात बताई. करीना ने कहा कि वे अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई योजना नहीं बनाती. बचपन में ही उन्होंने बड़ी फिल्म स्टार बनने की बात सोची थी. वे कहती हैं...*मैं कभी भी योजना नहीं बनाती. मनीष मेरा भाई है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है. मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती. जो दिल कहता है वो करती हूं. सिर्फ एक बार बचपन में मैंने फिल्मों का बड़ा सितारा बनने की बात सोची थी.*

करीना की तारीफ करते हुए मनीष बताते हैं... करीना से जब मैं पहली बार मिला तब वे नौ वर्ष की थीं. मैं करिश्मा और उनकी मम्मी से मिलने गया था. करिश्मा से जब मैं बात कर रहा था तब यह छोटी लड़की (करीना) जिसके छोटे बाल थे हमारी बातें पूरे ध्यान से सुन रही थी. शायद वह पूछना चाह रही थी कि मेरी स्टाइलिंग कब करोगे? उसी दिन मुझे लगा था कि यह लड़की फिल्मों में नाम कमाएगी.■

ऐश्वर्या ने रखी शर्त

सलमान के साथ काम करने को तैयार

ऐश ने कहा कि वह सलमान के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिल्म की कहानी और डायरेक्टर दोनों ही असाधारण होना चाहिए.

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखने की आस उनके फैंस को कब से है. इस जोड़ी को चाहने वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है. ऐश्वर्या ने सलमान के साथ काम करने के लिए हामी भर दी है, पर साथ ही एक शर्त भी रखी है.

जानकारों की मानें तो ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के साथ में काम करने की अड़चनें दूर हो गई है. दोनों ही पुरानी बातें भुलाकर साथ काम करने को तैयार हैं. बताया जा रहा है कि सलमान के साथ काम करने के सवाल पर ऐश्वर्या ने हामी भरी है.

जानकारी के मुताबिक एक इंटरव्यू में ऐश ने कहा कि उनको सलमान के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है. अभिनेत्री ने कहा, वह सलमान के साथ काम कर सकती हैं लेकिन उसके लिए फिल्म की कहानी और डायरेक्टर दोनों ही असाधारण होना चाहिए.

बताया जा रहा है कि सलमान को भी ऐश से कोई दिक्कत नहीं है. जानकारी के मुताबिक ऐश्वर्या अपनी आने वाली फिल्म *ऐ दिल है मुश्किल* के प्रमोशन के लिए सलमान खान के शो बिग बॉस में जा सकती हैं.■

अगले साल जनवरी में रिलीज़ होगी विद्या बालन की बेगम जान

श्रीजीत मुखर्जी इस फिल्म से बॉलीवुड में निर्देशन की पारी शुरू कर रहे हैं. बेगम जान एक वेश्यालय की विस्थापित महिलाओं की दुख भरी कहानी है. फिल्म में विद्या बेगम जान की शीर्षक भूमिका में हैं.

विद्या बालन अभिनीत आगामी फिल्म *बेगम जान* अगले साल जनवरी में रिलीज़ होगी. फिल्म आज़ादी से पहले के समय की कहानी है जिसका निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी कर रहे हैं. मुखर्जी इस फिल्म से बॉलिवुड में निर्देशन की पारी शुरू कर रहे हैं. *बेगम जान* एक वेश्यालय की विस्थापित महिलाओं की दुख भरी कहानी है. फिल्म में विद्या बेगम जान की शीर्षक भूमिका में हैं. फिल्म की निर्माता कंपनी प्ले इंटरटेनमेंट के प्रमुख मिलिंद दाबके ने एक बयान में कहा कि फिल्म 6 जनवरी, 2017 को रिलीज़ होगी. *बेगम जान* में नसीरुद्दीन शाह, रजत कपूर, गौहर खान, पल्लवी शारदा, ईला अरुण, आशीष विद्यार्थी और चंकी पांडे जैसे कई दूसरे कलाकार काम कर रहे हैं.■

बॉलीवुड न्यूज़

बेटे की हीरोइन ढूंढ़ने दिल्ली आएंगे सनी देओल

सनी देओल अपने बेटे करण देओल को अभिनय के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं. अपने बड़े बेटे की पहली फिल्म का निर्देशन एक्शन स्टार सनी देओल खुद करेंगे. जल्दी ही सनी अपनी टीम के साथ दिल्ली जाएंगे जहां पर वे हीरोइन की तलाश करेंगे.

सनी देओल जल्द ही अपने बेटे के लिए एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं. फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ़ने के लिए कुछ नियम सनी ने बनाए हैं. वह दिल्ली की होनी चाहिए और उसकी उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए. तो दिल्ली की लड़कियों, हो जाओ तैयार, बॉलीवुड में एंट्री के लिए.■

अक्षय कुमार ने छोड़ी फाइव

कुछ सप्ताह पहले ख़बर आई थी कि *मैरीकॉम* और *सरबजीत* बनाने वाले फिल्म निर्देशक उमंग कुमार अब अक्षय कुमार को लेकर फिल्म *फाइव* बनाने वाले हैं जिसमें अक्षय पांच भूमिका करने वाले हैं, लेकिन अब खिलाड़ी कुमार इस फिल्म से अलग हो गए हैं. तारीखों की समस्या के चलते अक्षय कुमार को यह फिल्म छोड़नी पड़ी.

इस समय अक्षय *जॉली एलएलबी* में व्यस्त हैं. अक्षय अपने ख़ास निर्देशक नीरज की फिल्म को पहले करना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने *फाइव* छोड़ दी है. 2017 में अक्षय पूरे वर्ष व्यस्त रहेंगे.■

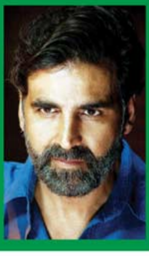

बाहुबली-2 22 अक्टूबर को दिखेगी पहली झलक

एस. राजमौली की आगामी फिल्म *बाहुबली : द कॉनक्ल्यूजन* का आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है. यह फिल्म पिछले साल रिलीज़ हुई *बाहुबली : द बिगनिंग* की सीक्वल है.

फिल्म के लोगो के साथ एक हैशटैग WKKB भी जारी किया गया है, जो *वाय कटप्पा किल्ड बाहुबली* यानी *कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?* के लिए है. राजमौली ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि फिल्म का पहला लुक अभिनेता प्रभास के जन्मदिन के एक दिन पहले यानी 22 अक्टूबर को जारी होगा. राजमौली ने संवाददाताओं को बताया, हम फिल्म की शूटिंग दिसंबर तक पूरी कर लेंगे. अभी इसके कुछ दृश्यों और दो गानों की शूटिंग का काम बाकी है. यह फिल्म 28 अप्रैल, 2017 को रिलीज़ होगी.■